राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

उज्जैन : बाबा महाकाल को बांधी गई राखी, सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को कर्नाटक का दौरा करेंगे

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 227 | रायपुर | रविवार 10 अगस्त 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

पीएम मोदी ने मनाया रक्षाबंधन, बच्चों को दुलारा, महिलाओं से बंधवाई राखी

एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, जहां स्कूली बच्चों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया, जहां स्कूली बच्चों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए कई स्कूलों से छात्राएं आईं। इस दौरान पीएम मोदी ने छोटी बच्चियों के साथ हंसी मजाक भी करते दिखे। पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए कई स्कूलों से छात्राएं आईं। इस दौरान पीएम मोदी ने छोटी बच्चियों के साथ हंसी मजाक भी करते दिखे।

पीएम मोदी ने राखी बांधने आई छोटी बच्चियों को गले लगाकर प्यार और दुलार किया। प्रधानमंत्री ने स्कूल छात्रों से राखी बंधवाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। पीएम मोदी ने राखी बांधने आई छोटी बच्चियों को गले लगाकर प्यार और दुलार किया। प्रधानमंत्री ने स्कूल छात्रों से राखी बंधवाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

वायुसेना चीफ का खुलासा : एस-400 ने पाक के लड़ाकू विमान किये थे ढेर

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट भारत ने मार गिराए थे

एजेंसी

इंडियन एयर फोर्स चीफ एपी सिंह बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एयर फोर्स चीफ एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। यह सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड है।

एपी सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल एलएम कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया, पाकिस्तान हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। उन्होंने कहा,

'हाल ही में खरीदे गए S-400 सिस्टम गेम-चेंजर रहे हैं। पाकिस्तान लंबी दूरी के ग्लाइड बम होने के बाद भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाया।'

एयर फोर्स चीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान के बहावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। वहां कुछ नहीं बचा था। ये तस्वीरें न सिफ सैटेलाइट से ली गईं। बल्कि लोकल मीडिया ने भी तबाह हुई बिल्डिंग की अंदर की तस्वीरें दिखाई थीं।

सेना को खुली छूट दी गई थी: सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना था। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। हमें खुली छूट थी। हमने तय किया कि कितना आगे बढ़ना है। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आजादी थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था। CDS के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया। वह हमें एकसाथ लाने के लिए मौजूद थे।

90 घंटे की जंग में PAK पीछे हटा: यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें (पाकिस्तान) साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी इसलिए वे आगे आए और हमारे DGMO को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं। हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया।

बालाकोट के भूत से छुटकारा पाया: 2019 में जब बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की तो उसके सबूत नहीं जुटा पाए। लोगों ने सवाल उठाए कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम थे और हम दुनिया को यह बताने में सक्षम थे कि हमने क्या हासिल किया है।

दुनिया हमें इकोनॉमी नहीं अध्यात्म के कारण विश्वगुरु मानती है : संघ प्रमुख मोहन भागवत

एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ये विश्व भारत को बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जानता है. ये बात मोहन भागवत ने नागपुर के शिव मंदिर में एक कार्यक्रम के दौरान कही. भागवत ने कहा कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है, इसलिए हमारा देश महान है. सभी के साथ भारत खुशियां बांटता है. साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान पर भारत को सभी देश विश्वगुरु मानते हैं.

'विश्व में मौजूद हैं कई अमीर देश' मोहन भागवत आगे कहते हैं कि, '3 लाख करोड़ की इकोनॉमी भारत जल्द ही बन जाएगा, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है. दूसरे देश जैसे चीन, अमेरिका इसे हांसिल कर चुके हैं. इस विश्व में अमेरिका, चीन के साथ कई देश अमीर हैं. पर भारत जैसा आध्यात्मिक ज्ञान किसी देश के पास नहीं है.'

'अपनी संस्कृति का करें पालन' मोहन भागवत ने कहा कि, 'इकोनॉमी भी जरूरी है पर भारत आध्यात्मिक ज्ञान के मौर्चे पर ही विश्व गुरु बन सकता है. जब हम अपने सभी त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे, अपनी संस्कृति का अच्छे से पालन करेंगे, तब जाकर आध्यात्मिक ज्ञान में इजाफा हो सकता है ।

चुनाव आयोग ने देश भर की 334 पार्टियों पर गिराई गाज, रद्द किया रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली. एजेंसी। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली के शुद्धीकरण की दिशा में शनिवार (9 अगस्त) को एक अहम कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया है. कर छूट जैसे विशेषाधिकार और लाभ हासिल करने वाले इन दलों ने 2019 से पिछले छह सालों में एक भी चुनाव लडऩे की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया, जिसके मद्देनजर इन दलों को पंजीकृत सूची से आयोग ने हटा दिया.

यह दल देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं. देश में सभी राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत हैं. इस प्रावधान के तहत किसी भी संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, उसे कर छूट जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ मिलते हैं.

2019 के बाद नहीं लड़ा कोई चुनाव यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ करने और ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से संचालित की गई है, जिन्होंने 2019 के बाद से कोई भी लोकसभा या राज्य-केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा या उपचुनाव नहीं लड़ा है और जिनका वास्तविक रूप से पता नहीं लगाया जा सका है. इस कदम राजनीतिक प्रणाली में शुद्धता लाने के मकसद से उठाया गया है. निर्वाचन आयोग ने जून में इस दिशा में कदम बढ़ाए थे. तब यह गौर किया गया था कि ECI में पंजीकृत 3 हजार से ज्यादा ईसीआई में से करीब साढ़े 300 अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं कर रही हैं. इसके बाद आयोग ने ऐसे आरयूपीपी की पहचान के लिए एक राष्ट्रव्यापी कसरत शुरू, जिसके बाद 345 ऐसे आरयूपीपी की पहचान सामने आई.

कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पार्टी अनुचित रूप से लिस्ट से बाहर न हो जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के CEO को ऐसे आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद इन पार्टियों को संबंधित CEO द्वारा सुनवाई के माध्यम से एक अवसर दिया गया. सभी का पक्ष जानने के बाद यह सामने आया कि 334 पार्टियां पिछले 6 सालों में एक भी चुनाव नहीं लड़ी हैं. ऐसे में उनके दल को सूची में शामिल नहीं रखा जा सकता।

तो पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाएगा अभी देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं. चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभ्यास उसकी ओर से जारी रखा जाएगा. सभी राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट हैं और अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल चुनाव नहीं लड़ती तो उसको पंजीकृत पार्टियों की सूची से हटा दिया जाएगा।

आईसीआईसीआई बैंक का बड़ा निर्णय, अब खाते में कम से कम 50 हजार रुपए रखना अनिवार्य

नई दिल्ली. एजेंसी

आईसीआईसीआई बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है. बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट्स के लिए मिनिमम एवरेज अमाउंट में भारी बढ़ोतरी की है. सेविंग अकाउंट में रखने वाले न्यूनतम राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है. मिनिमम बैलेंस में बढ़ोतरी मेट्रो से लेकर गांव तक के कस्टमर्स के लिए किया गया है. प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक के बचत खाते में अब मिनिमम बैलेंस 50 हजार बनाए रखना होगा. यह नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी माना जाएगा. पहले यह अमाउंट 10 हजार रुपये था. अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

रेलवे का बंपर फेस्टिवल ऑफर : आने-जाने का टिकट एक साथ लेने पर मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

नई दिल्ली. एजेंसी

इस त्यौहारी सीजन में सुरक्षित यात्रा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी सौगात का ऐलान किया है. इसके मुताबिक अगर आप आने और जाने दोनों का एक साथ टिकट करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसको लेकर रेल मंत्रालय ने राउंड ट्रिप पैकेज की शुरुआत की है.

त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में भारी भीड़ और टिकट की मारामारी से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई स्कीम शुरू की है. इसका नाम है राउंड ट्रिप पैकेज फॉर फेस्टिवल रश, इस स्कीम का मकसद है यात्रियों को सस्ती दर पर आने-जाने का टिकट देकर भीड़ को अलग-अलग दिनों में बांटना ताकि यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो सके.

इन यात्रियों को मिलेगी इस स्कीम की छूट - रेलवे के मुताबिक, इस स्कीम के तहत अगर कोई यात्री आने और जाने दोनों तरफ का टिकट एक साथ बुक करता है तो वापसी के सफर के बेस किराए पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. छूट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो आने और जाने का टिकट एक ही नाम और डिटेल्स के साथ बुक करेंगे. दोनों टिकट एक ही क्लास और एक ही स्टेशन जोड़ी के होने चाहिए. आने का टिकट: 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए होना चाहिए. जबकि वापसी का टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए हो।

विदेश | अब खत्म हो गया 35 साल पुराना संघर्ष?

अजरबैजान-आर्मेनिया ने खत्म की 40 साल पुरानी दुश्मनी

एजेंसी - वाशिंगटन - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार व्हाइट हाउस में अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच शांति समझौता कराने में सफल रहे। अज़रबैजान और आर्मीनिया के नेताओं ने व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर ट्रंप की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता दक्षिण कॉकस क्षेत्र में चार दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करता है। ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं का हैंडशेक कराकर यह समझौता कराया।

खत्म होगा 40 साल पुराना संघर्ष

अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच करीब 40 साल से संघर्ष चल रहा था। अब उम्मीद है कि यह युद्ध खत्म होगा।

इस समझौते में दोनों देशों के बीच प्रमुख परिवहन मार्गों को फिर से खोलने का प्रावधान है। इसके साथ ही अमेरिका को इस क्षेत्र में रूस के घटते प्रभाव का लाभ उठाने का अवसर भी मिलेगा। व्हाइट हाउस ने बताया कि इस समझौते के तहत एक नया ट्रांज़िट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा ÷ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी÷ (अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप मार्ग)।

ट्रंप हुए गौरवान्वित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मार्ग का नाम अपने नाम पर रखे जाने को ÷एक बहुत बड़ा सम्मान बताया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा, मैंने इसके लिए कोई मांग नहीं की थी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह नाम रखने का सुझाव आर्मीनिया की ओर से आया था। संयुक्त समझौते के अतिरिक्त दोनों देशों ने अमेरिका के साथ अलग-अलग समझौते भी किए हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा, तकनीक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि इन समझौतों के विस्तृत ब्योरे अभी जारी नहीं किए गए हैं।

डोभाल ने पहले पुतिन से और फिर की रूस के उप-प्रधानमंत्री से मुलाकात

डोभाल ने रूस के उप-प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर की बात

भारत स्थित रूसी दूतावास के अनुसार, डोभाल और मंतुरोव की मुलाकात शुक्रवार को हुई। दूतावास ने एक पोस्ट में कहा, ''इस बैठक के दौरान भारत-रूस के बीच सैन्य-तकनीकी सहयोग से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही असैन्य विमान निर्माण, धातु उद्योग और रासायनिक उद्योग जैसे अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने पर भी बातचीत हुई।'' डोभाल ने बृहस्पतिवार को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

एजेंसी

मॉस्को: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात करने के बाद अब प्रथम रूसी उपप्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। यह वार्ता भारत और रूस के बीच सैन्य-तकनीकी संबंधों और रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आधारित रही। इसके अलावा वैश्विक स्तर के मामलों व भारत-रूस के रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के इरादे से भी इस बैठक को आयोजित किया गया।

डोभाल की रूस में मौजूदगी में पुतिन ने की पीएम मोदी से बातत

बता दें कि डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने और इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी के लिए रूस में हैं। इसी दौरान शुक्रवार को पुतिन और पीएम मोदी ने फोन पर करीब 1 घंटे तक अहम वार्ता की। इससे भारत और रूस के गहराते संबंधों का पता चलता है। पुतिन और पीएम मोदी की यह फोनवार्ता ऐसे अहम समय में हुई है, जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 फीसद तक पहुंच गया है।

रूस के साथ भारत जारी रखेगा सहयोग डोभाल ने कहा कि बाहरी दबाव के बावजूद रूस के साथ सभी मोर्चों पर भारत अपना सहयोग जारी रखेगा। भारत और रूस के बीच यह जुगलबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और परेशान कर सकती है। ट्रंप वैसे भी भारत से सबसे ज्यादा खफा इसीलिए हैं कि वह अमेरिका को रोकने के बावजूद खुल्लम-खुल्ला रूस से तेल खरीद रहा है। भारत स्पष्ट रूप से कई बार वैश्विक मंचों पर भी कह चुका है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। भारत के इस जवाब से अमेरिका को अपनी भारती बेइज्जती महसूस हो रही है।

7 साल बाद मोदी की बीजिंग यात्रा से बेहद खुश चीन, बोला-SCO सम्मेलन बनेगा 'एकजुटता और दोस्ती' का मंच

एजेंसी

चीन ने इस महीने के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तियानजिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित यात्रा का शुक्रवार को स्वागत किया। उसने उम्मीद जताई कि यह आयोजन ''एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का समागम'' होगा। दिल्ली में मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने इस सप्ताह बताया कि सात साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। उनसे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन यात्रा की खबरों के बारे में पूछा गया था। चीन 31 अगस्त से एक सितंबर तक तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा, ''हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का एक संगम होगा, तथा एससीओ अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा।''

लोकशक्ति www.lokshakti.in

दो से अधिक बार शराब की तस्करी में संलग्न पाए जाने पर संबंधित की सम्पत्ति विरूपण की करें कार्यवाही : उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री ने किया जिले में की जा रही नवाचार एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

जशपुरनगर, संवाददाता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जिला प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा के द्वारा जिले में की जा रही नवाचार एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में लिया गया। इस अवसर पर विधायक चित्रकोट श्री विनायक गोयल, महापौर श्री संजय पांडेय, सचिव पंचायत श्री भीम सिंह, कलेक्टर श्री हरिस एस, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी श्री उत्तम गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि दो से अधिक बार शराब या नशा के अन्य स्रोत की तस्करी में संलग्न पाए जाने पर संबंधित की सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नशा संबंधी मामलों के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ दवा के व्यापारियों की बैठक करें । मंत्री ने सुपर हॉस्पिटल में ओपीडी संचालन को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के प्रमुख मार्गों के किनारे के ग्राम पंचायतों में काम्प्लेक्स निर्माण के तहत अच्छी दुकानें- परिसर बनाए ताकि पंचायत को राजस्व की प्राप्ति हो सके।अविवादित बंटवारा के प्रकरणों से पंचायत के प्रस्ताव पर राजस्व के रिकार्ड में दर्ज करने के लिए पंचायत सचिवों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दी जाए और जागरूकता अभियान के लिए होर्डिंग लगवायें, मुनादी भी करवायें। उन्होंने कहा कि मिलेट्स के किसानों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पाद को मार्केट तक पहुँचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें । जिले के मक्का उत्पादन किसानो को स्प्रिंकलर और अन्य विभागीय योजनाओं से भी प्रोत्साहन देने की पहल करने कहा।

बैठक में पूर्व के बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा किया गया साथ ही जिले में पंचायत विभाग के द्वारा किया गया नवाचारों और प्रस्तावित नवाचार, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत नवाचार की जानकारी दी गई। इसके अलावा अविवादित नामांतरण, बंटवारा ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत में पंजीयों के संधारण की स्थिति, अटल डिजीटल सुविधा-सीएससी भवन की जानकारी, अटल सुविधा केंद्र में लेनदेन की जानकारी, महतारी सदन स्वीकृति की समीक्षा, दीनदयाल अंत्योदय योजना का संकुल संगठनों के माध्यम से फंड फ्लो की जानकारी,दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएमएल) अंतर्गत नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।

जिला मिशन प्रबंधन इकाई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कलस्टर हेतु प्रस्तावित गतिविधि, डीपीआरसी पंचायत ट्रेनिंग सेंटर की स्थिति, मोर गांव- मोर पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आत्म समर्पित एवं नक्सल पीड़ित हितग्रहियों के प्रथम किश्त प्राप्त उपरांत आवासों की स्थिति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, मनरेगा के कार्यों, इसके अलावा मनरेगा आंगनबाड़ी भवन और पीडीएस भवन निर्माण कार्य की समीक्षा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आगामी तीन माह में किए जाने वाले बड़े कार्य हेतु लक्ष्य तथा कार्ययोजना की समीक्षा किए।

पत्नी और बेटी की हत्या करने की नियत से हमला करने वाले पति को हुआ आजीवन कारवास

भानुप्रतापपुर, संवाददाता।

थाना के कच्चे चौकी अंतर्गत ग्राम टेकाढ़ोहा निवासी नंद किशार बढ़ई ने पत्नी की चरित्र शंका के चलते और 02 साल की बेटी पर ढाई साल पहले लोहे के वसूला से हत्या की नियत से हमला बोला था, जिसमें दोनो की जान बच गई। अपर सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सीमा तिवारी ने बताया कि टेकाढ़ोहा निवासी नंद किशोर बढ़ई लगभग ढाई साल पहले 5 एवं 6 फ रवरी 2023 की दममियानी रात को लगभग साढ़े 11 बजे से लेकर पौन पाँच बजे सबसे पहले अपनी पत्नी संगीता बढ़ई के पेट और सिर पर वसूला से हमला किया और मरते दम तक पीटकर लहूलहान हालत में यह समझकर छोड़ दिया कि उसकी मौत हो गई, उसके उपरांत 02 साल की बेटी तृषा बढ़ई पर भी लोहे के वसूला से सिर पर जोरदार हमला बोला, जिससे दो साल की बेटी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। घटना की जानकारी जैसे तैसे आरोपी के पत्नी के परिजनों को 6 फरवरी को पता चला। परिजनों ने तत्काल ईलाज के लिए भर्ती कराया और घटना की जानकारी पुलिस को दिया। मौके पर कच्चे चौकी से पुलिस पहुँचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल पत्नी के रिश्तेदार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 307, 302 आईपीसी के तहत भानुप्रतापपुर थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय पेश किया और जेल भेजा गया। अपर लोक अभियोजकके अनुसार भानुप्रतापपुर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश भानुप्रतापपुर दीपक के. गुप्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए मिले साक्ष्य के आधार पर 07 अगस्त को आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत ।

आज से उपराष्ट्रपति पद के नामांकन प्रक्रिया शुरू

आदिमजाति मंत्री रामविचार नेताओं के दिल्ली जाने पर अटकलों का बाजार गर्म

रायपुर, लोकशक्ति

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही अब नई दिल्ली में आदिवासीनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिया है। जिसके चलते अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है, लेकिन राज्य के आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम इस समय दिल्ली में दिल्ली प्रवास पर हैं। जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफ दे दिया है। जिसके पश्चात मीडिया में अनेक राजनेताओं का सुखियों में आ गया है। छत्तीसगढ़ से विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का नाम चर्चा में है लेकिन इन दोनों ने इसका खंडन कर दिया है। एनडीए के पास पूर्व बहुमत है, लोकसभा और राज्यसभा में इनके पर्याप्त सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए राज्यसभा के सचिव को चुनाव अधिकारी बना दिया है।

छत्तीसगढ़ के आदिमजाति विभाग के मंत्री रामविचान नेताज आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही अब राजनीतिक महकमों में चर्चा है कि वे आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए निर्वाचन आयोग के अनुसार आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 से 22 जांच होगी, 25 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव होंगे। अन्यथा एनडी प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाएगा।

इधर राजधानी में रामविचाम नेताम के दिल्ली प्रवास को लेकर तरह-तरह की चर्चा व्याप्त है। आदिमजाति कल्याण विभाग का कार्य देख रहे रामविचार नेताम के सदस्यों का कहना है कि वे आदिमजाति विभाग में गए हुए हैं। और वे आदिवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे। याद रहे रामविचार नेताम राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे चुके हैं। वे झारखंड सहित अनेक राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। जिसके कारण आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान है।

बेटे ने टांगी से अपनी मां की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

जशपुर, लोकशक्ति

जशपुर जिले के थाना तुमला क्षेत्रांतर्गत ग्राम फरदबहार में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की टांगी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी बरामद कर लिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रार्थी सुबरन राम (उम्र 70 वर्ष), निवासी फरदबहार, थाना तुमला, जिला जशपुर, ने पुलिस को बताया कि दिनांक 06 अगस्त 2025 को उनकी बहन दशमती बाई और उनका भांजा कमल राम (उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गौरीघाट, थाना फरसाबहार) उनके घर मेहमान के रूप में आए थे। दोपहर में खाना खाने के बाद, दशमती बाई घर की परछी में चटाई बिछाकर लेटी हुई थी, जबकि सुबरन राम अपने कमरे में आराम कर रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे सुबरन राम को आंगन से अपनी बहन और भांजे के बीच झगड़े की आवाज सुनाई दी। जब वे आंगन में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कमल राम अपनी मां दशमती बाई के गले पर टांगी से लगातार वार कर रहा था। सुबरन राम के शोर मचाने पर आरोपी टांगी छोड़कर भाग गया। दशमती बाई की मौके पर ही गले में गहरी चोट के कारण मृत्यु हो गई। सुबरन राम की शिकायत पर तुमला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। थाना तुमला में धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, शव का पोस्टमार्टम कराया, और कुछ ही घंटों में आरोपी कमल राम को हिरासत में ले लिया।

जिला पंचायत सीईओ ने बहुउद्देशीय सेन्टरों का किया निरीक्षण

यहां संचालित होने वाली गतिविधियों को जल्द शुरू करने के दिए निर्देश

जशपुरनगर, संवाददाता

जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार ने विगत दिवस बहुउद्देशीय सेन्टर कुटमा, रोकडापाठ जामुनजोबला, सामरबार झुमराडुमर, सारूढाब और लेदरीपाठ सन्ना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इन समस्त सेन्टरों में संचालित होने वाले कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि इसका लाभ यहां के निवासियों को मिल सके। बहुउद्देशीय सेन्टर कुटमा के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का रोस्टर बना कर ड्यूटी लगाने एवं बीएमओ को 02 दिनों में मिनी पीएसी के रूप में समस्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही सेन्टर में सीएससी अटल डिजीटल केंद्र का संचालन कार्य गुरूवार तक प्रारंभ करने, बाउण्ड्री के अंदर पौधा रोपण करने, कीचन गार्डन, सेन्टर के मेन गेट में संस्था का नाम एवं बाउण्ड्रीवाल में आदिवासी कल्चर को प्रदर्शित करती हुई लेखन एवं पेंटिंग करने के निर्देश दिए। बहुउद्देशीय सेन्टर रोकडापाठ जामुनजोबला निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग को 01 सप्ताह के भीतर अपना कार्य प्रारंभ करने को कहा। इसके साथ ही सेन्टर के प्रांगण में पौधा रोपण एवं कीचन गार्डन तैयार करने, अटल डिजीटल सेन्टर का संचालन करने एवं महिला स्व सहायता समूह को अपनी गतिविधि शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनमन के तहत स्वीकृत 43 आवासों में से 27 आवासों में डोर लेबल तक के कार्य को 02 दिवस के भीतर शुरू कर ढलाई कराने हेतु सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया। जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार बहुउद्देशीय सेन्टर सामरबार झुमराडुमर निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने भवन में नवीन टाईल्स लगाने चित्रकला कार्य, दीवाल लेखन, बाउण्ड्रीवाल के अंदर पौधा लगाने आदि कार्यों को 15 अगस्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सरगुजा संभागीय अग्रवाल महासभा की कार्यकारिणी घोषित

संभाग के छह जिलों के अग्रज कार्यकारिणी में शामिल

17 अगस्त को शपथ ग्रहण व सामान्य सभा

सूरजपुर, सरगुजा संभागीय अग्रवाल महासभा के संभागीय अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल ने निर्वाचन के उपरांत छह जिले की 28 सभाओं का प्रवास व रायशुमारी के उपरांत संभागीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जिसमें निवृतमान संभागीय अध्यक्ष श्रीनिवास केडिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री गौरीशंकर अग्रवाल, महासचिव सुनील अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, कार्यालय उपाध्यक्ष सीए आशीष अग्रवाल, प्रमुख सलाहकार राजीव अग्रवाल, संयुक्त महासचिव मुकेश गर्ग, विकास अग्रवाल व श्याम सुंदर पोद्दार के साथ संभागीय महिला अध्यक्ष सीमा अग्रवाल तथा संभागीय युवा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल को मनोनित किया गया है। वहीं सभी जिलों के संभागीय उपाध्यक्ष में सुभाष अग्रवाल कोरिया, रामबाबू अग्रवाल एमसीबी, जगदीश अग्रवाल जशपुर, महेश अग्रवाल बलरामपुर, अंकुर गर्ग सूरजपुर व शुभम अग्रवाल सरगुजा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सचिव के रूप में मनोज अग्रवाल जशपुर, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल बलरामपुर, मनोज अग्रवाल कोरिया, राधेश्याम अग्रवाल एमसीबी, मनोज जैन सरगुजा, प्रमोद जैन सूरजपुर, पिताम्बर अग्रवाल सरगुजा, राजेश अग्रवाल बलरामपुर व कृष्ण कुमार गर्ग जशपुर जिले के सचिव नियुक्त हुए हैं। सह सचिव सुभाष अग्रवाल, खाजांची अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, अजय केडिया, विजयराज अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, निलेश अग्रवाल, अमित जिंदल, जयभगवान अग्रवाल के साथ सलाहकार समिति धनसीराम अग्रवाल, मदनलाल अग्रवाल, अरविंद सिंघानिया, प्रयागराज अग्रवाल, सज्जन अग्रवाल, रामचन्दर अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, मनीष कुमार अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल व केवल अग्रवाल शामिल हैं। अग्र पंचायत समिति अमृत लाल अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, मोहनलाल गोयल, जय भगवान अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, आनंद मित्तल व मोहनलाल अग्रवाल शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य समिति में सुभाष गोयल, सुभाष अग्रवाल, राधेश्याम जिंदल, पवन अग्रवाल, सज्जन कुमार अग्रवाल, नवीन कुमार अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, सचिन केडिया, पवन गर्ग, प्रियंक अग्रवाल तथा अजय अग्रवाल, शिक्षण समिति में कृष्ण कुमार अग्रवाल, प्रवीण गर्ग, आशीष अग्रवाल, ललित गोयल, रूपेश मित्तल, अजय अग्रवाल, भोलेनाथ गोयल, मुकेश गर्ग को शामिल किया गया है। विधिक समिति में केके अग्रवाल, एके गोयल, दुर्गा दास अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जय गोपाल अग्रवाल, राजेश गोयल व प्रदीप गर्ग शामिल हैं। बायोडाटा समिति में विनोद अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, संजय केजरीवाल, सुदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, विनेद अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, प्रितुल अग्रवाल सहित मीडिया समिति में प्रवेश गोयल, राजेश अग्रवाल, अरूण अग्रवाल व आदर्श बंसल के साथ संभागीय भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, महामंत्री विनोद कुमार, उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष जगदीश केडिया होंगे।

संभाग के अति विशिष्ट विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रहल्लाद राय अग्रवाल, रामअवतार अग्रवाल, भीमसेन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, बाबूलाल गोयल, व्हीके अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, डॉ.विष्णुदत्त अग्रवाल, संजय मित्तल, शिव कुमार अग्रवाल के साथ पदेन संरक्षक व संरक्षक मण्डल में चरण सिंह अग्रवाल, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, कश्मीरीलाल अग्रवाल, रमेशचंद अग्रवाल, विशंभरदयाल अग्रवाल, निरंजन अग्रवाल, सत्यनारायण मित्तल, रमन अग्रवाल, रामलाल अग्रवाल संरक्षक होंगे।

मेंकॉज में भालू के हमले से घायल जवान से मुलाकात की

जगदलपुर, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान आज शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज डिमरापाल पहुंचे, जहां आईईडी विस्फोट में घायल ग्रामीण व भालू के हमले से घायल जवान से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना।

विजय शर्मा सबसे पहले एसआईसीयू पहुंचकर प्रमोद से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी लेते हुए पूछा कहां तक पढ़े हो, जमीन का पट्टा है कि नहीं, धान कहां से खरीदते हो, कहां बेचते हो, तमाम मुद्दों पर बात करते हुए जानकारी ली। घायल ने बताया कि गांव में किसी के पास भी पट्टा नहीं है, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने घायल को अपना नंबर देते हुए फोन लगाने की बात कही, साथ ही घायल को छुट्टी होने के बाद गांव जाने पर जमीन का अधिकार पट्टा दिलाने की बात कही।

ग्रामीण से मिलने के बाद विजय शर्मा घायल जवान के पास पहुंचे। जवान ने बताया कि वह जिस टीम में चल रहा था, उसमें चौथे नंबर पर था, तीन जवानों के निकलने के बाद भालू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यहां से ठीक होकर आओ, फिर मैदान में मिशन को पूरा करेंगे। इस दौरान घायलों को फूलों का भी वितरण किया गया।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष वेदप्रकाश पांड़े के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी, एसपी शलभ सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग भी मौजूद रहे।

विशेष नवजात शिशु देखभाल ईकाई बीमार नवजात शिशुओं की बचा रही जान

जशपुरनगर,

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में जशपुर जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल ईकाई एस.एन.सी.यु. के प्रभारी व शिशु रोग विषेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंह व उनकी टीम के द्वारा बीमार नवजात शिशुओं को ना सिर्फ अति आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है वरन बीमार नवजात शिशुओं की जान बचाकर उनके परिवार में नयी उम्मीद और खुशियां दी जा रही है। इसी क्रम में माह अक्टूबर 2024 मे जिला चिकित्सालय जशपुर में भर्ती कांसाबेल के ग्राम-खुटीटोली निवासी श्रीमती कंचन का प्रसव समय से पूर्व गर्भधारण के 30वें सप्ताह जनवरी 2025 में हो जाने के कारण बच्चा श्वसन संबंधी विकार आर.डी.एस. जैसेः- सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े के संक्रमण, रक्त मे ऑक्सीजन की कमी व न्यूनतम वजन मात्र 940 ग्राम के साथ जन्म हुआ। बच्चे की अवस्था व जीवन के प्रति संघर्ष को देखते हुए उसके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। जिसके कारण बच्चे को जिला चिकित्सालय में संचालित विशेष नवजात शिशु देखभाल ईकाई, एस.एन.सी.यू. में भर्ती कराया गया। जहां बच्चे की जीवन की रक्षा व शारिरिक विकास के लिये उसे सर्फेक्टेंट थेरेपी फेफड़े के विकास के साथ-साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन सर्पोट, फिडिगं ट्युब के माध्यम से पोषण, तापमान नियंत्रण हेतु इनक्यूबेटर आदि सुविधायें लगभग 58 दिनों तक दिया गया। इस दौरान बच्चे को नियमित रूप से डॉ गौरव सिंह एवं एस.एन.सी.यु. स्टॉफ सुश्री कमला, प्रियंका, अंजली, दीपांजली व अन्य सहयोगी स्टॉफ द्वारा देखभाल, उपचार व बच्चे के माता-पिता को परामर्श सुविधा प्रदान किया गया।

बच्चे की माता श्रीमती कंचन ने बताया कि एस.एन.सी.यू. में बच्चे की देखभाल व उपचार के कारण डेढ़ माह के भीतर बच्चे का वजन 1.24 किलो ग्राम हो गया। बच्चा मॉ का दूध पीने में सक्षम नहीं था जो 58 दिन के देखभाल उपरांत दूध पीने में ना सिर्फसक्षम हो चुका बल्कि अब उसे सांस लेने मे भी तकलीफनहीं है। आज सात माह के नियमित देखभाल व मासिक फॉलोअप उपरांत बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जिस हेतु जिला चिकित्सालय में मिली सुविधा व देखभाल के लिए श्रीमती कंचन ने चिकित्सक डॉ गौरव सिंह सहित सभी स्टॉफ को हृदय से धन्यवाद दिया। डॉ गौरव ने साथ ही बताया कि हर शनिवार को जिला चिकित्सालय में ऑटिज्म, बच्चों के स्वभाव से संबंधित समस्याओं, अतिसक्रिय बच्चों, विकासात्मक देरी युक्त बच्चों हेतु विशेष क्लिनिक का संचालन विगत माह जून 2025 से निरंतर किया जा रहा है। उक्त विशेष क्लिनिक के संचालन से जशपुर जिलें के बच्चों के साथ साथ जशपुर जिलें के सीमावर्ती राज्यों से संलग्न जिलों के बच्चों को भी लाभ मिल रहा है।

विद्युत विभाग ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में शिविर लगाकर लोगों को दी जानकारी

लोकशक्ति

जशपुर, संवाददाता ।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पत्थलगांव एवं कुनकुरी में शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें विद्युत वितरण कंपनी के समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, वाहन मालिकों ने भाग लिया।

वितरण कंपनी पत्थलगांव के शिविर में कार्यपालन यंत्री एस पी मरकाम के द्वारा सभी को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया ।उनके द्वारा सभी को सोलर पैनल लगाने हेतु प्रेरित किया गया, एवं मिलने वाला सब्सिडी के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही साथ बैंक फाइनेंस करने की भी संपूर्ण जानकारी दी गई। उक्त शिविर में कार्यपालन यंत्री के अतिरिक्त सहायक यंत्री श्री मनीष कुमार खत्री, कनिष्ठ यंत्री पत्थलगांव श्री कुल रंजन मिंज,एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित हुए। श्री एसपी मरकाम के द्वारा बताया गया कि 1 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार के द्वारा 30 हजार एवं राज्य सरकार के द्वारा 15 हजार का अनुदान दिया जाता है, 2 किलो वाट का सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा 60 हजार एवं राज्य सरकार द्वारा 30 हजार का अनुदान दिया जाता है इसी तरह 3 किलो वाट या उससे अधिक का सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान 78000 एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 30000 का अनुदान दिया जाता हैं। कुनकुरी में आयोजित शिविर में सहायक यंत्री श्री लोक नाथ नेताम, कनिष्ठ यंत्री कुनकुरी श्री गिरधर कुमार, कनिष्ठ यंत्री दुलदुला श्री अनिल साय, कनिष्ठ यंत्री तपकरा श्री रामपाल कंवर, एवं बिलिंग प्रभारी श्री रिजवान उल हक उपस्थित होकर योजना का विस्तृत जानकारी दिया गया।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने 195 करोड़ की राशि मंजूर की केन्द्र सरकार ने

छत्तीसगढ़ को आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत सहायता राशि स्वीकृत

रायपुर, संवाददाता।

वामपंथी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे और संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 195 करोड़ की केंद्रीय सहायता राशि वामपंथी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत की है। यह स्वीकृति वित्त मंत्रालय की जस्ट-इन-टाइम फंड रिलीज़ प्रणाली के अनुसार सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉडल के तहत की गई है।

यह मदर सैंक्शन सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से बनाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय के विरुद्ध धनराशि की रिलीज़ के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड किया गया है। कुल 195 करोड़ में से 190.6125 करोड़ कार्यक्रम निधि और 4.3875 करोड़ प्रशासनिक निधि के रूप में स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किया जाएगा। स्पर्श दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी समय केवल एक सक्रिय मदर सैंक्शन प्रणाली पर मान्य रहेगा, जबकि पूर्व के बैलेंस को सक्रिय सैंक्शन में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

यह राशि छत्तीसगढ़ के सुदूरवर्ती, वनवासी एवं वामपंथी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए प्रदान की गई है। कार्यों में नवीन ऑल-वेदर ग्रामीण सड़कें, मौजूदा सड़कों का सुदृढ़ीकरण, तथा सेतु एवं क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो बाढ़ग्रस्त हैं अथवा वर्षा ऋतु में पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इन सड़कों से बस्तियों को ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा, जिससे शासन व्यवस्था, सेवा वितरण और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में सुधार होगा। इस योजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जशपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

4.3875 करोड़ की प्रशासनिक निधि का उपयोग मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन ,तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, तथा एमआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाटा प्रबंधन हेतु किया जाएगा।

यह स्वीकृत राशि पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत समायोजित की गई है। बैच-I (2019-20) के तहत 56.82 करोड़ वर्तमान सैंक्शन से समायोजित किए गए हैं, जिससे उस बैच के तहत अब कोई शेष राशि नहीं बची है। वहीं, बैच-I (2022-23) के अंतर्गत 133.79 करोड़ समायोजित किए गए हैं, जिससे 217.39 करोड़ की राशि आगामी रिलीज़ के लिए शेष रहेगी। इस समायोजन में पूर्व में जारी राशि एवं अर्जित ब्याज को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें संशोधित मदर सैंक्शन और सिंगल नोडल एजेंसी-स्पर्श के माध्यम से ई-बिल क्लियरेंस भी शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों के त्वरित उपयोग को सुनिश्चित करे। साथ ही, वित्त मंत्रालय के 13 जुलाई 2023 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(1) के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना पूर्ण होने पर राज्य को सभी सिंगल नोडल एजेंसी खातों को बंद कर अपरीक्षित केंद्रीय अंश को भारत की समेकित निधि में वापस करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, राज्य अंश की अपरीक्षित राशि को राज्य की समेकित निधि में एवं राज्य कोष में रखे गए किसी भी केंद्रीय अंश को CFI में लौटाया जाना चाहिए।

स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा, शैक्षणिक कार्य प्रभावित

0-रायपुर जिले के 22 शालाओं में 73 शिक्षकों की भर्ती के लिए संविदा नियुक्ति की जाएगी

0-11-12 अगस्त को शहीद स्मारक शाला भवन फाफाडीह में होगा दस्तावेज सत्यापन

रायपुर, लोकशक्ति

शिक्षा संचालनालय के आदेश में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शीघ्र ही संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य में हजारों की संख्या में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोल दिए गए है। यहां पर प्राचार्य व्याख्याताओं के नहीं होने के कारण इस स्कूल के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। राजधानी में सरोना, महोबा बाजार, शहीद स्मारक फाफाडीह, आरडी तिवारी आमापारा, डीपी पूजारी राजातालाब तथा लालपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों का टोटा बना हुआ है। इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा संविदा पदों की भर्ती, दावा आपत्ति, निराकरण पश्चात दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम प्रवीण्य सूची तैयार की जाएगी। ज्ञात रहे राजधानी में इस समय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। राजधानी में आर डी तिवारी, वीपी पूजारी तथा सरोना, राजातालाब, लालपुर, मोवा में इन स्कूलों का संचालन हो रहा है। यहां पर मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन इस स्कूल को डीएम फंड से संचालित किया जाता है, जिसके कारण इन स्कूलों का भविष्य अधड़ में लटक गया है। शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती लेकिन उन्हें नियमित भुगतान नहीं हो पाता इसलिए सत्ता बदलते ही इन विद्यालयों को पीएम श्री में बदलने की स्कीम चलाई जा रही है। इसलिए इसके पालक इसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जिलाधीश के निर्देश पर शालाओं में प्रवेश तथा अन्य प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से की जाती है। इन स्कूलों का आकर्षण बढ़ने के कारण मध्यम वर्गीय परिवार जहां प्रवेश के लिए लोग माननीय विधायकों, सांसदों से अनुशंसा पत्र लिखाकर आते हैं।

अंधड़ चलने से विद्युत की आंख-मिचौली से उपभोक्ता परेशान

रायपुर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के पश्चात वर्षा होने का पूर्वानुमान है, इधर राजधानी में त्यौहारी सीजन में खरीददारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां पर आए दिन मौसम साफ रहता है और शाम होते ही वर्षा शुरू हो जाती है। तेज अंधड़ के साथ वर्षा होने के कारण इस समय विद्युत की आंख मिचौली चल रही है, जिससे विद्युत उपभोक्ता परेशान हैं।

मौसम विभाग तथा विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होती है, जिसका असर इस समय विद्युत व्यवस्था पर पड़ रहा है। राजधानी में शाम होते ही स्ट्रीट लाईट नहीं जलती विशेषकर जीई रोड में भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। वहीं कई घरों में विद्युत प्रवाह नहीं हो पता, जिसके कारण विद्युत उपभोक्ता परेशान रहते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर फिरोजपुर, चंडीगढ़ और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर हिमालय की तराई के पास से होते हुए उत्तर पूर्व अरुणाचल तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बांग्लादेश के मध्य भाग में 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

प्रदेश में कल दिनांक 8 अगस्त को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः चरम उत्तर छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। 12 अगस्त से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने की संभावना है ।

मंत्री श्री कश्यप ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

विभागीय कार्यों में आ रही तकनीकी समस्याओं का आपसी समन्वय से करें निराकरण: मंत्री श्री केदार कश्यप

लोकशक्ति

रायपुर, 05 अगस्त 2025/ विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण आपसी समन्वय स्थापित कर समय-सीमा में निराकरण करें। यह बातें जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज शिवनाथ भवन अटल नगर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने बैठक में जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि एमआईएस में आ रही समस्याओं का आपसी समन्वय स्थापित कर 19 अगस्त 2025 के पूर्व समस्त तकनीकी विषयों पर आवश्यक निर्णय लेते हुए निराकरण कर लिया जाए। साथ ही तकनीकी स्वीकृति से संबंधित वित्तीय अधिकार को युक्तियुक्त करने हेतु प्रस्ताव 06 अगस्त 2025 तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निविदा प्रपत्र के अंतर्गत 108 प्रकरणों में दोषी पाये गये निविदाकारों के विरूद्ध कार्यवाही एक सप्ताह

के भीतर अनिवार्यतः पूर्ण करें और दोषी पाए गए निविदाकारों को आगामी निविदा में भाग लेने के संबंध में निविदा कंडिका में संशोधन हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

बैठक में सचिव श्री टोप्पो ने अधिकारियों को एमआईएस में संबंधित प्रविष्टी प्रदर्शित होने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निविदा प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का संबंधित मुख्य अभियंता एवं निविदा प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता आपस में समन्वय स्थापित कर निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि बोधघाट वृहद् परियोजना, इन्द्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना, शेखरपुर जलाशय एवं डांडपानी जलाशय के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही पूरी कर तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में निविदा स्वीकृति का कार्य निर्धारित 100 दिवस की समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने बैठक में जलाशयों से कृषकों की माँग के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने विभिन्न विषयों पर विभागीय नीति तैयार कर एक माह के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जल-कर में वृद्धि हेतु प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग के कार्य को भी पी.पी.पी. माध्यम से कराए जाने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सचिव श्री टोप्पो ने मंत्री श्री कश्यप को बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और परियोजना मण्डल की आगामी बैठक हेतु आवश्यक तैयारियां एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही भी समय से पूर्ण कर लिया जाएगा।

अलग-अलग क्षेत्र से दो दोपहिया वाहन पार

रायपुर, (आरएनएस)। अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने दो दोपहिया वाहन पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में बाजार चौक गोगांव निवासी जीतेन्द्र कुमार ध्रुव 43 वर्ष ने उरला थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एमएक्स 7908 को बुधवारी बाजार उरला के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में ग्राम फरफौद निवासी आकाश ढीढी 21 वर्ष ने गुढ़ियारी थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 पीयू 6865 को रामनगर ओव्हर ब्रीज के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 20 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है।

प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजितः छात्रावास और स्कूल के 161 बच्चों की हृदय रोग संबंधी स्क्रीनिंग

रायपुर, लोकशक्ति

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार तथा जिला प्रशासन रायपुर की नवाचारी पहल ÷प्रोजेक्ट धड़कन÷ के अंतर्गत आज शासकीय प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, सरोरा एवं आडवाणी आर्लीकन स्कूल में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान, जांच और निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करना है।

शिविर के दौरान सरोरा स्थित छात्रावास में 12 छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई, जबकि आडवाणी आर्लीकन स्कूल में कुल 149 बच्चों की जांच की गई, जिनमें 54 छात्र और 95 छात्राएं शामिल रहीं। कुल मिलाकर आज 161 बच्चों की हृदय रोग संबंधी प्रारंभिक जांच की गई।

जांच के दौरान 1 बच्चा संदिग्ध (सस्पेक्टेड) पाया गया, जिसे *विशेष परीक्षण* हेतु श्री सत्य साईं अस्पताल, नवा रायपुर भेजा जा रहा है। प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत, बच्चों में तेज़ धड़कन, वजन न बढ़ना, शरीर में नीलापन, बार-बार सर्दी-खांसी, सांस लेने में परेशानी, स्तनपान के दौरान पसीना आना जैसे लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संभावित हृदय रोगों की समय रहते पहचान की जा सके।

0-नगर निगम ने उच्च न्यायालय के निर्देशा का पालन करने कहा

पशु पालकों को पशुओं को घर में बांधकर रखने निगम अधिकारियों की हिदायत

रायपुर,

नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 6 कार्यालय में जोन 6 कमिश्नर हितेन्द्र यादव ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी अदिव्य हाजरी की उपस्थिति में जोन 6 के सभी 7 वार्डों के समस्त पशुपालको की बैठक लेकर उन्हें आवारा पशुओं के कारण सड़को पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन में राज्य शासन और जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देश पर प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया।

नगर निगम जोन 6 जोन कमिश्नर ने सभी पशु पालको को अपने पशुओ को अपनी गौशालाओं में बांधकर रखने एवं सड़क पर खुले में किसी भी हालत में नहीं छोड़ने की कड़ी हिदायत दी। अन्यथा की स्थिति में विधि अनुरूप कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी सभी पशुपालको को दी है। जोन 6 जोन कमिश्नर ने पशु पालको को नाली में गोबर नहीं बहाए जाने की सख्त हिदायत दी है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही कर ई जुर्माना वसूलने की स्पष्ट चेतावनी दी है। यहां उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिए गए आदेश के पालन हेतु राज्य शासन एवं रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में विभिन्न सडक मार्गो में काउकेचर वाहन और विशेष टीम की सहायता से सभी 10 जोनो के समस्त वार्डो के विभिन्न प्रमुख स्थानो पर लगातार अभियान चलाकर सडक से पशुओ को घरपकड़ कर गौठान कांजी हाउस भेजा जा रहा है एवं आयुक्त के निर्देश पर सभी जोन कमिश्नरो द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम अपर आयुक्त स्वास्थ्य श्री विनोद पाण्डेय एवं नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रीति सिंह प्रतिदिन निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे है।

प्रत्येक शनिवार को शासकीय कर्मचारियों को अवकाश देने का अधिकृत आदेश नहीं होने से अधिकारी पशोपेश में

पीएचक्यू में तोड़ मरोड़कर आदेश जारी होने से बढ़ रहा रोष

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साधी

रायपुर, संवाददाता

महानदी मंत्रालय, इन्द्रावती संचालनलाय एवं विभिन्न जिलों में जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कार्यरत शासकीय कर्मी शासन द्वारा प्रत्येक शनिवार को अवकाश देने के निर्णय को लेकर पशापेश में हैं। शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई अधिकृत आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय में तोड़ मरोड़कर आदेश जारी कर दिया गया है। जिसकों लेकर शासकीय कर्मचारियों में और भी रोष बढ़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा सरकार आते ही सत्ता में पिछली भूपेश सरकार के कई आदेशों को पलट दिया गया, भूपेश सरकार में प्रत्येक शनिवार को भी शासकीय अवकाश दिया जाता था, लेकिन विष्णु देव सरकार ने पिछले सरकार के कई आदेशों को पलट दिया है। नेताओं का कहना है कि प्रति शनिवार को अवकाश देने से कोई मतलब नहीं है। द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को ऐसे भी अवकाश रहता है। इसलिए अलग शनिवार को छुट्टी देने की आवश्यकता नहीं है।

सामान्य प्रशासन से नहीं निकला आदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं निकाला गया है, अधिकारियों के अनुसार पुलिस मुख्यालय में ही यह आदेश निकला है, लेकिन इसे तोड़ मरोड़कर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जब आदेश जारी किया जाएगा, तभी इसे सत्य माना जाएगा।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

राहुल आरोपों का शपथ पत्र क्यों नहीं देते?

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि जिन वोटर्स के नाम, पते और पहचान को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं, उसका प्रमाण शपथ पत्र के साथ दें। सबसे बड़ी बात ये है कि वोटिंग का तरीका secret होता है। ये भी secret होता है कि किसने किसको वोट दिया। फि र राहुल गांधी किस आधार पर ये दावा कर सकते हैं कि जिनके नाम उन्होंने गिनाए, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया?

सबसे दिलचस्प बात ये है कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतादाता सूची के विशेष गहन परीक्षण का विरोध कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग जांच नहीं करेगा, तो voter list दुरुस्त कैसे होगी? अगर कर्नाटक की list में राहुल गांधी को गड़बड़ दिखी, वहां ठीक से list नहीं बनी, तो बिहार में voter list की checking पर ऐतराज़ कैसे किया जा सकता है?

बुजुर्ग वट वृक्ष का घना साया।

आया जब भी वट वृक्ष का घना साया,
बुजुर्ग हाथ मेरे शीश पर हमेशा पाया।

चेहरे की सलवटे नहीं आशीष लकीरें
उनसे बच्चों का चेहरा सदा मुस्कुराया।

मैंने जब शिद्दत से उनका स्मरण किया,
जीवन को सार्थक पथ पर अपना पाया।

चेहरा मुस्कुराता उनका जब मुझे याद आया,
फिर जीवन में नही कभी भी जरा घबराया।

चलने से लेकर बढ़ने तक हर समय
मुशीबतों से मुझे उन्होंने सदा बचाया।

साथ हों कर लो उनकी सम्पूर्ण सेवा
पछताना मत फिर क्या खोया-पाया।

उनका अंश उनका अभिमान हो तुम,
अर्पित करो जो तुमने उनसे सारा पाया।

सुबह शाम प्रणाम नमन करो उन्हें,
जीवन तुमने उन्हीं से समूचा पाया।

बुजुर्ग माता-पिताओं को सदा मेरा नमन,
ईश्वर से पहले उनने जीवन मेरा बनाया।

सभी बुजुर्गों को प्रणाम-नमन।

संजीव ठाकुर

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन
PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp
Modimaya_ Vaidik_Netritva
Rashtriya Ekta
DLF-Vadra-Bhrasht Tantra
Silent Assassins Jan11,1966
Accursed & Jihadi Neighbour

प्रकृति के पुत्र और संस्कृति के प्रहरी हैं आदिवासी

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त, केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि यह सभ्यता की जड़ों और संवेदनशीलता के स्रोत को स्मरण करने का दिन है। यह दिन न केवल आदिवासियों के अस्तित्व, अधिकारों यानी जल, जंगल, जमीन और उनके जीवन की रक्षा का उद्घोष है, बल्कि यह नए भारत के पुनर्निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करने का भी अवसर है। आदिवासी समाज कोई पिछड़ा समूह नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर पर्यावरण रक्षा तक, सामाजिक समरसता से लेकर आध्यात्मिक परंपराओं तक, हर दिशा में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है।

आदिवासी प्रकृति के पुत्र और संस्कृति के प्रहरी है। 'जो प्रकृति से जुड़ा है, वही मनुष्यत्व का संरक्षक है'-यह वाक्य आदिवासी समाज पर अक्षरशः लागू होता है। आदिवासी शब्द मात्र एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि एक दर्शन है, सहजता, सामूहिकता, संतुलन और सह-अस्तित्व का दर्शन। करीब 90 प्रतिशत खनिज सम्पदा, वनौषधियां और जैव विविधता इन्हीं के क्षेत्रों में विद्यमान है। उनका जीवन सभ्यता के केंद्र से नहीं, बल्कि संवेदना के मूल से संचालित होता है। वे भले ही 'वनवासी' कहलाए गए, परंतु उनका जीवन दर्शन हमें शहरीकरण के आडंबर से बाहर निकालकर स्वाभाविक जीवन की राह दिखाता है। नए भारत में विकास का पर्याय यदि केवल बहुराष्ट्रीय निवेश, चकाचौंध और स्मार्ट सिटी बन गया है, तो आदिवासी समाज उसके विस्थापित मूल्य हैं। जल-जंगल-जमीन के नाम पर किए गए सौदे, खनिज लूट, धार्मिक कन्वर्जन, सांस्कृतिक विघटन और जबरन भूमि अधिग्रहण की घटनाएं केवल उनकी आर्थिक दशा ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति, भाषा और परंपरा को भी निगलती जा रही हैं। आज आदिवासी समाज ऋण, अशिक्षा, पलायन, अस्वास्थ्यकर जीवन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। तथाकथित विकास ने उन्हें 'पराया' बना दिया है। वे भारत में रहकर भी अपने ही देश में अदृश्य नागरिक बन गए हैं, जिनके पास न राशन कार्ड है, न पहचान पत्र, न ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शक्ति।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए भारत की कल्पना में अगर ÷सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास÷ का सूत्र वाक्य सार्थक करना है, तो आदिवासी पुनर्जागरण सबसे पहली शर्त है। इस दिशा में गुजरात के प्रसिद्ध जैन संत गणि राजेन्द्र विजयजी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन आदिवासी क्षेत्रों के लिए संघर्ष, सेवा और सद्भाव की त्रयी बन गया है। वे वर्षों से आदिवासी समाज के उत्थान हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, नशामुक्ति, रोजगार और संस्कृति संवर्धन के अभियान चला रहे हैं। उनका ÷सुखी परिवार अभियान÷ केवल परिवार को नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज को जागृत करने का एक जनांदोलन बन चुका है। वे आदिवासियों में आत्मबल, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता की भावना जगा रहे हैं। बालिका शिक्षा केंद्र, नैतिक शिक्षा अभियान, युवाओं के लिए स्वावलंबन कार्यशालाएं, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, आदिवासी ग्रामोद्योग, आदिवासी संस्कृति उन्नयन और स्व-सहायता समूहों का गठन-ये सभी उनके प्रयासों का हिस्सा हैं। वे जनजातीय समाज में अहिंसा, नैतिकता और भारतीय संस्कृति के बीज बो रहे हैं, ताकि वे अपने मूल से कटे नहीं, बल्कि गौरव से जुड़े रहें।

आज आदिवासी समाज को जितना खतरा बाह्य आर्थिक और राजनीतिक शोषण से है, उससे कहीं अधिक सांस्कृतिक अस्मिता के विघटन से है। धर्मान्तरण की गतिविधियाँ न केवल धार्मिक परिवर्तनों का परिणाम देती हैं, बल्कि उससे जुड़ी मानसिक गुलामी और राष्ट्र-विरोधी मानसिकता भी पनपती है। गणि राजेन्द्र विजयजी इस खतरे को भली-भांति समझते हैं। उन्होंने धर्मान्तरण के विरुद्ध शांति, संवाद और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का मार्ग अपनाया है। उन्होंने जैन धर्म के मूल्यों के साथ-साथ सभी धर्मों के सकारात्मक मूल्यों को आदिवासी जनजीवन से जोड़ा है ताकि वे किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक हिंसा से बचें। गणिजी का स्पष्ट मत है कि हर आदिवासी को अपनी जड़ों में झांकना होगा। उसे यह पहचानना होगा कि वह केवल वनवासी नहीं, अपितु संस्कृति का संवाहक है।' वे आदिवासियों को आत्म निरीक्षण की प्रेरणा देते हैं कि ÷जो अपने मूल से कट जाता है, वह किसी भी विकास का अधिकारी नहीं बन सकता।÷ उनकी प्रेरणा से कई आदिवासी युवाओं ने शिक्षा ग्रहण की, रोजगार स्थापित किए, कुटीर उद्योगों की ओर बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मगौरव को पुनः प्राप्त किया।

आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार की ओर अग्रसर हो रही है, तब आदिवासी समाज को भी इस बदलाव की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। तकनीक उनके जीवन में केवल बदलाव का कारक नहीं, बल्कि संरक्षण और सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है। एआई आधारित भाषाई अनुवाद तकनीकों से उनकी बोली और लोककथाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सकता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक विरासत विश्व तक पहुंचे। ड्रोन एवं जीआईएस तकनीक से आदिवासी क्षेत्रों के भू-अधिकार सुरक्षित किए जा सकते हैं। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, टेलीमेडिसिन और डिजिटल शिक्षा से वे दुर्गम क्षेत्रों में भी उन्नत जीवन स्तर पा सकते हैं। नवाचार तभी सार्थक होगा जब वह जंगलों में बसे एक युवा को भी ग्लोबल लर्निंग का अवसर प्रदान करे, न कि उसे अपनी जड़ों से काटे।

आज की वैश्विक दुनिया 'लोकल टू ग्लोबल' की सोच को प्रोत्साहित कर रही है और आदिवासी समाज इसमें एक अनमोल भागीदार बन सकता है। उनका पारंपरिक ज्ञान, जैविक खेती, वन औषधियों की समझ, हस्तशिल्प और पर्यावरण संतुलन की परंपराएं विश्व समुदाय के लिए एक वैकल्पिक जीवनदर्शन बन सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आदिवासी युवा आधुनिक शिक्षा को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति और जीवनमूल्यों से जुड़े रहें। उन्हें अपने उद्यमिता कौशल को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है, जैसे वनोपज आधारित उद्योग, इको-टूरिज्म, वन-हस्तशिल्प, संगीत-नृत्य उत्सव आदि के माध्यम से वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। डिजिटल मार्केट प्लेस के जरिए उनके उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में पहुंचाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा तभी पूर्ण होगी जब आदिवासी समाज भी अपने भीतर से आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़े।

भारत की स्वतंत्रता केवल मैदानों और दरबारों में नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहाँ आदिवासी वीरों ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी थी। बिरसा मुंडा जैसे अद्भुत योद्धा और आध्यात्मिक नेता ने न केवल अंग्रेजों के भूमि अधिग्रहण और धर्मान्तरण के विरुद्ध जनजागरण किया, बल्कि एक सशस्त्र संघर्ष को भी नेतृत्व प्रदान किया। झारखंड में चला उनका उलगुलान आंदोलन (महाविप्लव) आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान की एक ऐतिहासिक घोषणा थी। इसी तरह सिद्धू-कान्हू, रानी दुर्गावती, तेलंगाना के कोमराम भीम, भील आंदोलन के गोविंद गुरु, तेनालीराम बावरी, और नारायण सिंह जैसे अनेक आदिवासी सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि भारत की आज़ादी की चिंगारी सबसे पहले आदिवासी अंचलों में धधकी थी। बिरसा मुंडा और आदिवासी वीरों का आजादी में अविस्मरणीय योगदान रहा लेकिन दुर्भाग्यवश, इतिहास की मुख्यधारा में इनके योगदान को उतनी जगह नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी। आज विश्व आदिवासी दिवस हमें इन भूलाए गए नायकों को स्मरण करने, उनका गौरव गान करने और नई पीढ़ी में उनकी प्रेरणा जगाने का अवसर देता है।

विश्व आदिवासी दिवस एक प्रतीक दिवस है, परंतु नीति, नीयत और निष्ठा से इसका पालन आवश्यक है। केवल भाषण, घोषणाएं और योजनाओं से आदिवासी समाज नहीं बदलेगा। उन्हें सुनने, समझने और साथ चलने की आवश्यकता है। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकार की कानूनी एवं नैतिक सुरक्षा हो। उनकी भाषा, परंपरा और नृत्य-संगीत को संरक्षित किया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में उपलब्ध कराए जाएं। आदिवासी नेतृत्व को राजनीतिक सशक्तिकरण मिले। नया भारत आदिवासी आत्मा के बिना अधूरा है क्योंकि भारत की आत्मा आदिवासियों की थापों में बसती है, उनके ढोल, मांदर, बांसुरी, उनके लोकगीत, उनके नृत्य और उनकी सरलता में। यदि हमें नया भारत बनाना है तो हमें आदिवासी समाज के साथ खड़ा होना होगा, उनके लिए नहीं, उनके साथ। गणि राजेन्द्र विजयजी जैसे संत इस दिशा में दीपशिखा बनकर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस विश्व आदिवासी दिवस पर हम केवल स्मरण नहीं, संवेदना, संरक्षण और सहभागिता के साथ इस अद्वितीय समाज के साथ जुड़ें, यही होगा सच्चा राष्ट्रधर्म।

यह निजी विचार है।

प्रकृति के पुत्र और संस्कृति के प्रहरी हैं

विनीत नारायण

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूस से तेल और हथियारों की खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की घोषणा की।

यह कदम भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में महत्त्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था (डेड इकानमी) कह कर निशाना बनाया और भारत के उच्च टैरिफ और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं को इसका कारण बताया।

ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाली आक्रामक टैरिफ नीतियों को अपनाया है। 7 अगस्त, 2025 से लागू होने वाले 25 प्रतिशत टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने इसके लिए भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को प्रमुख कारण बताया। उनके अनुसार, भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है, जो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के समय में अस्वीकार्य है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ (जिसे उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक बताया) और गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाओं की भी आलोचना की। ट्रंप ने पहले 20-25 प्रतिशत टैरिफ की संभावना जताई थी, लेकिन अंतिम घोषणा में अतिरिक्त दंड भी शामिल किया गया। यह कदम भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, र प्रतिशत और आभूषण और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो अमेरिका के साथ भारत के व्यापार के महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।

कांग्रेस नेता और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के मृत अर्थव्यवस्था वाले बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, हां, ट्रंप सही हैं। हर कोई जानता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मृत है, सिवाय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के। मुझे खुशी है कि ट्रंप ने यह तथ्य सामने रखा। दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। भाजपा ने अडानी को मदद करने के लिए अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए, विशेष रूप से नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बताए। उन्होंने यह भी पूछा कि ट्रंप के भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर बार-बार किए जा रहे दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है?

कांग्रेस पार्टी ने इस टैरिफ को भारत की विदेश नीति की विफलता के रूप में चित्रित किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, राहुल गांधी ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी। यह टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था, निर्यात, उत्पादन और रोजगार पर असर डालेगा। हम अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स निर्यात करते हैं, और 25 प्रतिशत टैरिफ से ये महंगे हो जाएंगे जिससे मांग कम होगी और उत्पादन तथा रोजगार पर असर पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और टैरिफ को भारत के व्यापार, एमएसएमई और किसानों के लिए हानिकारक बताया। अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बताया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रंप को व्हाइट हाउस का जोकर कह कर उनकी आलोचना की।

वहीं, अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर मिश्रित राय व्यक्त की है। कुछ का मानना है कि इसका प्रभाव सीमित होगा जबकि अन्य ने दीर्घकालिक नुकसान की चेतावनी दी है। इंवेस्टमेंट इनफार्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया (इक्रा) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, प्रस्तावित टैरिफ और दंड हमारी अपेक्षा से अधिक हैं, और इससे भारत की जीडीपी की वृद्धि पर असर पड़ सकता है। प्रभाव की गंभीरता दंड के आकार पर निर्भर करेगी। अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया (ईवाई) के व्यापार नीति विशेषज्ञ अग्नेर सेन ने कहा, टैरिफ से समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, चमड़ा और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। ये क्षेत्र भारत-अमेरिका व्यापार में मजबूत हैं, और टैरिफ से इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। फाउंडेशन फार इकोनामिक डवलपमेंट के राहुल अहलूवालिया ने चेतावनी दी कि टैरिफ भारत को वियतनाम व चीन जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार, निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं के भारत की ओर स्थानांतरण की संभावना नहीं है।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आशावादी रुख भी अपनाया है। फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, हालांकि यह कदम दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे निर्यात पर असर डालेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह अल्पकालिक घटना होगी और दोनों पक्ष जल्द ही एक स्थायी व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सतर्क और संयमित रुख अपनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा, हम राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। भारत ने एक दशक में फ्रैजाइल फाइव से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएगा। एक सूत्र ने कहा, चुप्पी सबसे अच्छा जवाब है। हम बातचीत की मेज पर इस मुद्दे को हल करेंगे।

कुल मिलाकर 25 प्रतिशत टैरिफ और अतिरिक्त दंड ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की विफलता के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि अर्थशास्त्रियों ने इसके मिश्रित प्रभावों की ओर इशारा किया है। जहां कुछ क्षेत्रों पर तत्काल असर पड़ सकता है, वहीं भारत के पास अन्य बाजारों में विविधता लाने और बातचीत के जरिए समाधान खोजने का भी अवसर है। यह स्थिति न केवल आर्थिक, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक हितों को संतुलित करना होगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या से कैसे निपटती है।

(लेख में विचार निजी हैं)

मोदी एक बार कह दें कि ट्रंप ने जंग नहीं रूकवाई

अजीत द्विवेदी

संसद के मानसून सत्र का इंतजार सबको था। इंतजार इसलिए था क्योंकि सरकार ने पहलगाम कांड और आपेरशन सिंदूर के बाद विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की अपील पर ध्यान नहीं दिया था। संसद में खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने और देश के नागरिकों को इसकी सचाई बताने की बजाय सरकार दुनिया भर के देशों में डेलिगेशन भेज कर उनके सामने अपना पक्ष रख रही थी। तभी जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई और यह तय हुआ कि दूसरे हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार, 28 जुलाई को पहलगाम कांड व आपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी तो उम्मीद थी कि इनसे जुड़े समूचे घटनाक्रम की सचाई सामने आएगी। सरकार हर पहलू के बारे में जानकारी देगी। विपक्ष जो सवाल पहले से उठा रहा है और जो सदन में सवाल उठाए जाएंगे, उनका वस्तुनिष्ठ तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि दो दिन की लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के लंबे भाषण के बाद भी बहस अधूरी ही रह गई। इस बहस के बाद यह धारणा भी मजबूत हुई कि भारत में संसदीय बहसों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और सारी संसदीय बहस सिर्फ राजनीति साधने और चुनावी लाभ के लिए होती हैं। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में संसदीय बहसें ऐसी नहीं होती हैं। भारत में भी कोई संविधान सभा की बहस के दस्तावेज पढ़े तो उसे भी आज जो हो रहा है उस पर शर्म ही आएगी।

बहरहाल, पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर से जुड़े कौन से सवाल थे, जिनके वस्तुनिष्ठ जवाब की जरुरत थी, उस पर आने से पहले एक रूपक के जरिए इस बहस को समझते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति उनसे बिजली नहीं आने की शिकायत कर रहा था। वह व्यक्ति कह रहा था कि सिर्फ तीन घंटे बिजली आती है और अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर तक यह बात सुनने के बाद माननीय बिजली मंत्री ने अपने गले में पड़ी ढेर सारी मालाएं निकालीं और जोर से नारा लगाया, जय श्रीराम! बात वही खत्म हो गई। लोकसभा में पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर सत्तापक्ष यानी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के सभी नेताओं का भाषण इसी श्रेणी का था। सवालों का जवाब देने की बजाय सत्तापक्ष के लगभग सारे वक्ता सेना के शौर्य का गुणगान कर रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अपनी छाती ठोक रहे थे और 77 साल पहले वाली सरकार की कमियां गिना रहे थे।

सोचें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब एक सौ मिनट के भाषण में 14 बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम लिया! क्या पहलगाम कांड और आपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा में देश के लोग यही सुनना चाहते थे? नेहरू की गलतियां थीं या इंदिरा गांधी ने गलती की या उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने गलतियां कीं तभी तो देश की जनता ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को मौका दिया है! अब तो देश के लोग इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। नेहरू का या इंदिरा गांधी का नाम लेकर किसी भी तात्कालिक मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता है। नेहरू की गलतियां अपनी जगह हैं, जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी एक सौ साल से बोल रहे हैं। लेकिन लोग तो यह जानना चाहते थे कि पर्यटकों की उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पहलगाम घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात था? लोग यह जानना चाहते थे कि आतंकवादी 20 मिनट तक तांडव करते रहे और उतनी देर में एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचा और आतंकवादियों के जवाब देने के लिए एक भी गोली नहीं चली तो ऐसा क्यों हुआ? यह तो संभव नहीं है कि नेहरू या इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से रोक दिया था? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इतने लंबे भाषण में एक बार भी पहलगाम में मारे गए 26 बेकसूर नागरिकों का जिक्र नहीं आया। देश के लोग जानना चाहते थे कि आपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया तो फिर 88 घंटे के भीतर सीजफायर क्यों हो गया?

यह निजी विचार है।

गुजरात में विश्व शेर दिवस 2025 समारोह में 11 जिलों के लाखों विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे

पीआईबी

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से, 10 अगस्त, 2025 को विश्व शेर दिवस - 2025 मनाएगा। यह दिवस गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में मनाया जाएगा।

इस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, गुजरात के वन मंत्री श्री मुलुभाई बेरा, सांसद, राज्य के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गुजरात में, एशियाई शेर अद्वितीय

पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो केवल सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। प्रोजेक्ट लायन के तहत मंत्रालय और राज्य के निरंतर प्रयासों और गुजरात सरकार के नेतृत्व ने इस प्रतिष्ठित प्रजाति के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

'जंगल के राजा' - एशियाई शेर के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, 'विश्व शेर दिवस' का भव्य समारोह 10 अगस्त को गुजरात में सौराष्ट्र के 11 जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये राजसी जानवर सौराष्ट्र के 11 जिलों में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। गुजरात में शेरों की संख्या 2020 से 32% बढ़ी है, जो मई 2025 के शेरों की संख्या के अनुमान के अनुसार 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है।

बरदा वन्यजीव अभयारण्य पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में 192.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बरदा एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में उभर रहा है। 2023 में इस क्षेत्र में शेरों के प्राकृतिक प्रवास के बाद, शेरों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें 6 वयस्क और 11 शावक शामिल हैं। यह अभयारण्य महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट और एशियाई शेरों के संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र है। द्वारका-पोरबंदर-सोमनाथ पर्यटन सर्किट के निकट होने के कारण, बरदा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। लगभग 248 हेक्टेयर क्षेत्र में सफारी पार्क शुरू करने की योजना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। इस कार्यक्रम में लगभग 180.00 करोड़ रुपये की लागत से वन्यजीव संरक्षण कार्यों का भी शुभारंभ किया जाएगा।

मंत्री सोनोवाल ने पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की

काठमांडू, भारत सरकार में पोत, जहाज और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर काठमांडू पहुंचे हैं। सुबह विमानस्थल पर केंद्रीय मंत्री का नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने स्वागत किया। केन्द्रीय मंत्री सोनोवाल ने पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। मंदिर पहुंचने पर पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सदस्य सचिव डॉ. मिलन थापा ने उनकी अगुवाई की। पशुपतिनाथ मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद सोनोवाल ने वहीं पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। सोनोवाल पशुपति मंदिर क्षेत्र में आयोजित कोटि होम महायज्ञ में भी शामिल हुए। काली बाबा के नाम से मशहूर श्री 1008 कृष्णानंद जी महाराज के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया।

दिल्ली के जैतपुर में हरिनगर स्थित मोहन बाबा मंदिर के पास भारी बारिश के बीच एक दीवार गिरने के बाद मलबा हटाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है।

नई दिल्ली में भारी वर्षा के कारण यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने के बीच एक युवक डूबती नाव से पानी निकालता हुआ।

संचार साथी मोबाइल ऐप के डाउनलोड की संख्या लॉन्च के लगभग 6 महीने में 50 लाख के पार

जनभागीदारी दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफलड़ाई में सरकार की मदद कर रही है

संचार साथी मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है

पीआईबी

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की संचार साथी पहल ने दूरसंचार सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। लॉन्च के बाद से, इस मोबाइल ऐप ने छह महीनों के भीतर 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड प्राप्त कर लिए हैं। भारत की व्यापक भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, डीओटी ने अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करके ऐप की पहुँच का विस्तार किया है। धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्टिंग को और भी आसान बना दिया गया है, अब उपयोगकर्ता कुछ ही टैप में सीधे अपने कॉल और एसएमएस लॉग से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

अपनी शुरुआत से अब तक, संचार साथी पहल के तहत 5.35 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं, नागरिकों की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं, और चक्षु सुविधा के ज़रिए चिह्नित 29 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय किया गया है।

भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चतम स्तर

यह उपलब्धि भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत है: रक्षा मंत्री

पीआईबी

वित्त वर्ष 2024-25 में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन की तुलना में 18त्न की अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाती है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से अब तक 90त्न की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी को भी प्रदर्शित करती है, उस समय यह आंकड़ा 79,071 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को हासिल करने में रक्षा उत्पादन विभाग और सभी हितधारकों यानी कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं और निजी उद्योग के सामूहिक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने इस सफलता को भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) और अन्य पीएसयू का कुल उत्पादन में लगभग 77त्न योगदान रहा है, जबकि निजी क्षेत्र ने इसमें 23त्न की भागीदारी की है। भारत में रक्षा निवेश

के लिए निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024-25 में 23त्न हो गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 21त्न बढ़त को प्रदर्शित करती है। यह वृद्धि देश के डिफेन्स इकोसिस्टम में इस क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका को उजागर करती है।

रक्षा उद्योग जगत के कारोबार में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने वर्ष-दर-वर्ष लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसका श्रेय दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार करने की सुगमता में तेजी और पिछले दशक में स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान दिए जाने को जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू और निजी क्षेत्र का समग्र उत्पादन क्रमशः 16त्न तथा 28त्न बढ़ा है।

यह रिकॉर्ड स्थापित करने वाली उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों का महत्व बताती है। आयात पर निर्भरता कम करने और एक रक्षा औद्योगिक परिसर बनाने पर जोर देने से न केवल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, बल्कि इससे देश की निर्यात क्षमता भी बढ़ रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 21,083 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात आंकड़ों की तुलना में 2,539 करोड़ रुपये अर्थात 12.04त्न का उछाल है। भारत का रक्षा उत्पादन क्षेत्र सतत नीतिगत सहयोग, बढ़ी हुई निजी भागीदारी व विस्तारित निर्यात क्षमताओं के साथ आने वाले वर्षों में और भी तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है।

हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन

पीआईबी

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएबी) में भारत के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

मंत्री महोदय ने एनआईएबी में एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप-IV क्वार्टरों की आधारशिला भी रखी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल 19.98 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया है। यह बुनियादी ढाँचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और एक जीवंत शैक्षणिक एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा।

9,300 वर्ग फुट में फैले और ?1.85 करोड़ की लागत से निर्मित, पशु बायोबैंक की अत्याधुनिक सुविधा पशुओं के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगी। स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3डी बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायोस्टोरेज, ऑटोक्लेव रूम, उन्नत एयर हैंडलिंग सिस्टम और निर्बाध पावर बैकअप से सुसज्जित, यह प्रयोगशाला रोग मॉडलिंग,

ऊतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी।

डीबीटी-बीआईआरएसी के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) के समर्थन से, पशु स्टेम कोशिकाओं और उनके व्युत्पन्नों की बायोबैंकिंग को सक्षम करने के लिए सुविधा का विस्तार किया जाएगा।

मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भविष्यदर्शी दृष्टि की सराहना की, जिसके कारण जैव प्रौद्योगिकी बायोई3 नीति को लागू करना संभव हुआ, जिससे भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी होने का लाभ मिला।

इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाने और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए पांच नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण शुरू किए:

ब्रुसेलोसिस का त्वरित पता लगाना - ब्रुसेला प्रजातियों का शीघ्र और सटीक पता लगाने के लिए एक क्षेत्र-तैनात, डीआईवीए - सक्षम डायग्नोस्टिक किट।

मैस्टाइटिस का पता लगाने की तकनीक - डेयरी मवेशियों में सबक्लिनिकल और क्लिनिकल मैस्टाइटिस के लिए एक लागत प्रभावी ऑन-साइट निदानात्मक परख।

रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण उपकरण - एक पोर्टेबल उपकरण जो जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दो घंटे के भीतर परिणाम प्रदान करता है। टोक्सोप्लाज़मोसिस डिटेक्शन किट - पशुओं में टोक्सोप्लाज़मा गोंडी संक्रमण के लिए एक संवेदनशील और विशिष्ट परीक्षण।

जापानी एन्सेफलाइटिस डिटेक्शन किट - पशुओं और मनुष्यों में बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तीव्र पट्टी।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन नवाचारों से कृषि से जुड़ी जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि होगी और पशुपालन क्षेत्र में ÷सदाबहार क्रांति÷ का मार्ग प्रशस्त होगा।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ÷मुझे खुशी है कि डॉ. राजेश गोखले के नेतृत्व में पूरा जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत को भविष्य के लिए तैयार करने में योगदान दे रहा है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित अगली औद्योगिक क्रांति के आने पर हम पीछे नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था विनिर्माण से पुनर्योजी और आनुवंशिक प्रक्रियाओं की ओर बढ़ेगी, और भारत ने इस बदलाव की शुरुआत पहले ही कर दी है। नीति निर्माताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जैव ई3 नीति जैसी पहलों की दीर्घकालिक प्रासंगिकता को समझा है, के समर्थन के साथ यह सबसे अच्छे समय में से एक है।÷

उन्होंने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड (एएनआरएफ) के तहत हाल ही में घोषित 1 लाख करोड़ रुपये के आरडीआई फंड से निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास को विशेष बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष रैंक की ओर बढ़ सकेगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग पौधों, जानवरों और मानव जगत को एक ही छत के नीचे अनोखे ढंग से एकीकृत करता है। उन्होंने अंतरिक्ष विभाग के साथ सहयोग सहित अंतरिक्ष-आधारित प्रयोगों में भारत के योगदान का उल्लेख किया और अंतरिक्ष चिकित्सा एवं अंतरिक्ष शरीरक्रिया विज्ञान जैसे उभरते क्षेत्रों की परिकल्पना की।

कृषि के मोर्चे पर, उन्होंने कहा, ÷ये रिलीज़ पशु-आधारित कृषि उत्पादकता के एक नए चरण–एक 'सदाबहार क्रांति'–का प्रतीक हैं। कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का 18त्न और हमारे कार्यबल का 60त्न कृषि पर निर्भर है, इसलिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य में नवाचारों का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। कृषि अनुसंधान पर खर्च किया गया एक रुपया 13 का प्रतिफल देता है, और पहले दिन से ही उद्योग भागीदारों को जोड़ने से यह सुनिश्चित होता है कि ये तकनीकें ज़मीनी स्तर तक पहुँचें।

चुनाव व्यवस्था में सफाई: चुनाव आयोग ने 334 आरयूपीपी को सूची से हटाया

पीआईबी

देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्यीय/आरयूपीपी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1955 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं। वर्तमान में, चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। (अनुलग्नकः राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों की सूची) राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होंगे और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी बिना किसी देरी के आयोग को देनी होगी। इससे पहले, जून 2025 में, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

युवाओं के सपनों को लगेंगे पर, बनेंगे 34 नए नालंदा परिसर, दूरस्थ शहरों में भी खुलेंगी सेंट्रल लाइब्रेरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पर देने 34 नए नालंदा परिसर बना रही है। ये नालंदा परिसर केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बन रहे, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे शहरों में भी बन रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृत की है। वहीं रायगढ़ में सीएसआर से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम प्रगति पर है। इसके लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपए का करार हुआ है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा।

इन सेंट्रल लाइब्रेरीज-सह-रीडिंग जोन्स से प्रदेशभर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के करियर निर्माण में ये लाइब्रेरीज काफी मददगार और अहम साबित होंगे। इन सर्वसुविधायुक्त, अत्याधुनिक लाइब्रेरीज में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफ्लाइन पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने पिछले दो वर्षों में 33 नालंदा परिसरों के लिए 237 करोड़ 57 लाख 95 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसरों के लिए 125 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अलग-अलग शहरों में 15 नालंदा परिसरों के लिए 111 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 11 नालंदा परिसरों के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधित निर्माण एजेंसीज को कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। ये जल्द ही आकार लेना शुरू कर देंगे।

नगरीय प्रशासन विभाग ने 11 नालंदा परिसरों के लिए जारी किए 19.15 करोड़

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 11 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में कुल 19 करोड़ 14 लाख 87 हजार रुपए इसी महीने जारी किए हैं। विभाग द्वारा दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर नगर निगम को प्रत्येक को दो करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपए की प्रथम किस्त जारी की गई है। वहीं बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, कांकेर और जांजगीर नगर पालिका तथा कुनकुरी नगर पंचायत को प्रत्येक को एक करोड़ दस लाख 37 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में जारी किए गए हैं। नालंदा परिसर के निर्माण के लिए जशपुर नगर पालिका को दो करोड़ 85 लाख 57 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की गई है।

दस शहरों में 500 सीटर और 22 में 250 सीटर लाइब्रेरी बनेंगी राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अनुकूल माहौल देने के लिए दस नगरीय निकायों में 500 सीटर और 22 शहरों में 250 सीटर लाइब्रेरी बनाए जाएंगे। दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर और भिलाई नगर निगम तथा जशपुर, लोरमी एवं गरियाबंद नगर पालिका में 500-500 सीटर नालंदा परिसरों का निर्माण किया जाएगा। वहीं धमतरी और चिरमिरी नगर निगम, कवर्धा, जांजगीर-नैला, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, सक्ती, पेंड्रा, सारंगढ़, सूरजपुर, बैकुंठपुर, दंतेवाड़ा एवं सुकमा नगर पालिका तथा कुनकुरी, बसना और अंबागढ़-चौकी नगर पंचायत में 250-250 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन बनाए जाएंगे।

रायपुर में अभी तीन लाइब्रेरी संचालित, दो और बनेंगे राजधानी रायपुर में अभी तीन सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन संचालित हैं। इनमें एक हजार सीटर नालंदा परिसर-सह-ऑक्सी रीडिंग जोन, 800 सीटर तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-स्मार्ट रीडिंग जोन और 500 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों में नालंदा परिसर में पढ़ाई करने वाले 400 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर न केवल अच्छी नौकरियां हासिल की हैं, बल्कि प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी प्राप्त किया है। रायपुर में जल्दी ही एक हजार सीटर और 500 सीटर नई लाइब्रेरी का काम प्रारंभ होगा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इनके लिए क्रमशः 22 करोड़ 80 लाख रुपए और 11 करोड़ 28 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

नालंदा परिसर सिर्फ इमारत नहीं, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद ; विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के नालंदा परिसर की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिले, इसके लिए हम अलग-अलग क्षेत्र के शहरों में नालंदा परिसरों का निर्माण कर रहे हैं। सुकमा से लेकर सूरजपुर और रायगढ़ से लेकर कवर्धा तक हर कोने में अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी-सह-रीडिंग जोन खोले जा रहे हैं। ये नालंदा परिसर सिर्फ इमारत नहीं, युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने सभी सुविधाएं मुहैया कराने प्रतिबद्ध : साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशभर में नालंदा परिसरों के विस्तार के बारे में कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वसुविधायुक्त ये लाइब्रेरियां उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई का अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के साथ ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री भी प्रदान करेंगी। राज्य के युवाओं की मेहनत को उनके इच्छित मुकाम तक पहुंचाने में नालंदा परिसर बड़ी भूमिका निभाएंगे। यहां वे पूरे फोकस, लगन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

अगस्त क्रांति दिवस पर जिले के कांग्रेस जनों ने याद किया अमर शहीदों को

जांजगीर-चांपा /

अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन पर 9 अगस्त को देश को आजादी दिलाने वाले शहिद वीर योद्धाओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी,पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, , सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलाना आजाद जी ,राजेन्द प्रसाद जी , अरुणा आसफअली जी, सहित सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए शहीद स्मारक जांजगीर में जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप के विशेष उपस्थिति में एवं जिला कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश पैगवार के संयोजकत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर अगस्त क्रांति दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया , कार्यक्रम के प्रारंभ में अमर शहीदों को याद करते हुए धुप दीप प्रज्वलित कर शहीद स्मारक में पुष्पांजलि किया गया कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप जी,जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रमेश पैगवार , जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ परस शर्मा , पिछड़ा वर्ग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य लोकेश राठौर,सेवादल के जिला अध्यक्ष दैव कुमार पांडे, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भगवान दास गढ़वाल, रफीक सिद्दीकी,उत्तम पाटले , अनिल राठौर,राईस किंग खुटे, अनिल चौरसिया, मुस्कान परवीन, वर्षा सिंह, रामविलास राठौर, राजा सिद्धकी,विजय गढवाल, जनपद सदस्य राजू सूर्यवंशी ,परमेश्वर राठौर, दीपेंद्र कहरा,कमलेश ताम्रकार, अंशु यादव,सफीक खान,किसन कहरा अभिषेक सिंह, रवि सूर्यवंशी,चांद राठौर फरीद मोहम्मद, सफीक खान, नूतन राठौर, अतिक कुरैशी,रविकांत, रवि शंकर,सहित कांग्रेस जन शामिल हुए

छोटी बहन ने भैया को स्वयं की बनाई राखी बांधी

लोकशक्ति। बाराद्वार - भाई बहन के असीम प्रेम व अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर बाजार में रौनक बढ़ जाती है. चाहे वह राखी , कपड़े , मिठाई , गिफ्ट , या अन्य का दुकान क्यों ना हो सभी जगह खरीददारी जमकर होती है. बहनें भी अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखी खरीद कर अपने भाइयों की कलाई में विधि विधान के साथ राखी बांधती हैं .यहाँ भाई बहन के बीच स्नेह और सुरक्षा के उत्सव को यादगार बनाए रखने के लिए बाराद्वार नगर की बच्ची मानसी यादव जो कक्षा पांचवी की छात्रा है ने बाजार की राखी के बदले अपने हाथों से ऊनी व सूती धागे से आकर्षक राखी बनाकर अपने भैया के कलाई में बांधकर भैया के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित की है. जिसे देखकर भैया लोकित यादव के साथ साथ माता-पिता ने भी बच्ची की इस हुनर की प्रशंसा करते हुए उन्हें गिफ्ट प्रदान कर उनका उत्साह वर्धन किया।

2 साल पहले किए गए पुलिया निर्माण गुणवत्ताहीन, पिचिंग का कार्य अब तक अधूरा ग्रामीणों में आक्रोश

जांजगीर-चांपा

राजनांदगांव। शहर से लगे ग्राम सुंदरा से अचानकपुर मार्ग पर बनाए गए पुलिया निर्माण कार्य मे गुणवत्ताहीन कार्य होने के कारण, और कार्यों में की गई लापरवाही के चलते पिचिंग का कार्य अब तक अधूरा है।

ग्रामीणों ने बताया कि सुंदरा से अचानकपुर मार्ग पर लगभग 2 वर्ष पहले पुलिया निर्माण का कार्य किया गया है और पिचिंग का कार्य को अभी अंजाम दिया जा रहा है वह भी सिर्फ पत्थर को रख रहे हैं ना ही उसमें सीमेंट डाली जा रही है और ना ही उसको व्यवस्थित ढंग से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी शिकायत ग्रामीण जनों ने उच्च अधिकारियों के करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ग्रामीण जनों ने बताया कि ठेकेदार संजय सिंघी द्वारा बीते 2 वर्ष पूर्व यह पुल का निर्माण किया गया है और पिचिंग को सिर्फ एक तरफ अभी कर रहा है वह भी ग्रामीणों के बार-बार आग्रह के बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण क्षेत्रवासियो में भारी आक्रोश पनप रहा है।

लोगो के घरो मे पानी भर जाने से होती है परेशानी - ग्रामीणो ने आगे बताया कि ग्राम अचानकपुर बस्ती का पानी अधिक तथा निकासी हेतु पुल का व्यास कम होने से पानी वार्ड के घरों में घुस जाता है ग्रामीणों द्वारा पक्का पुलिया बनाने की मांग पर ठेकेदार द्वारा स्टीमेट में नहीं होना कहकर नहीं किया गया।

सरपंच संघ नें गज़माला से विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह जी का किया स्वागत

राजनांदगांव।

6अगस्त को छः ग विधानसभा अध्यक्ष मा.डॉ रमन सिंह जी राजनांदगाव के दौरे मे थे. इसी कड़ी मे स्पीकर सदन राजनांदगाव मे ब्लॉक् नवनिर्वाचित सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष मा. डॉ. रमन सिंह जी से भेट मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राजनांदगाव प्रथम बार सरपंच संघ क अध्यक्ष जितेंद्र साहू के प्रतिनिधित्व मे विधानसभा अध्यक्ष मान डॉ. रमन सिंह जी से मुलाकत कर गज माला के साथ स्वागत कर आशीर्वाद किया.।डॉ रमन सिंह जी नें सभी सरपंचो को ग्राम पंचायत के प्रति निःस्वार्थ रूप से काम करने क लिए शुभकामनायें दिए।अध्यक्ष जितेंद्र साहू के साथ ब्लॉक के सरपंचो के साथ मुलाकात कर अपने ग्राम के समस्याए एवं विकास हेतु मांग पत्र भी दिया। जिसमे जीतेन्द्र साहू(अध्यक्ष), डिल्लू रामट्ठ साह (उपाध्यक्ष) मलिमखम कोसरे (कोषाध्यक्ष) मुकेश साहू (संरक्षक), हिपेंद्रट्ठ डुसाह (संरक्षक), अभिषेक पाटिला(मिडिया प्रभारी) रामकिसून साहू, हीना घनश्याम साहू, बिसंतीन, कोमल टंडन ,गोविन्द वर्मा, नेताम, जीवन साहू,चित्ररेखा ठाकुर, नीलिमा शिवा साहू, रमाकांत, मनीष देव साहू, एवं अन्य सरपंच साथीगण उपस्थिति रहे।

रायपुर : पॉम की खेती से किसानों को मिलेगा आय का स्थायी जरिया

उद्यान विभाग की तकनीकी मदद से प्रदेश में पॉम की खेती को मिली रही नई दिशा

प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष ढाई से 3 लाख रूपए की आमदनी

एक बार लगाएं तीसरे वर्ष से 30 वर्षों तक लगातार उत्पादन पाएं

केंद्र और राज्य सरकार से एक-एक लाख रूपए का अनुदान

उद्यान विभाग की तकनीकी मदद से प्रदेश में पॉम की खेती को मिली रही नई दिशा

रायपुर, संवाददाता

पॉम की खेती प्रदेश के किसानों के लिए स्थायी आय का जरिया बन रही हैं। राज्य सरकार किसानों को अतिरिक्त आमदनी के साधन उपलब्ध कराने पॉम सहित अन्य उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दे रही है। वहीं पॉम ऑयल की मांग और उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए पॉम की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन के तहत साझा अभियान शुरू किया है। जिसके तहत 2 हजार 682 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पॉम पौधों का रोपण हो चुका है। पॉम ऑयल सबसे अधिक उपयोग में लाये जाने वाला वनस्पति तेल है। इसका उपयोग बिस्किट, चॉकलेट, मैगी, स्नैक्स और गैर खाद्य जैसे साबुन, क्रीम, डिटर्जेंट, बायोफ्यूल आदि उत्पादों में होता हैं। पॉम के कृषकों को प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक-एक लाख रूपए अनुदान भी दिया जा रहा है। वहीं किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं।

देश भर में 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पॉम का रोपण

केंद्र सरकार ने देश की खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता को कम करने और किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से नेशनल मिशन ऑन ईडएबल आयल के माध्यम से पाम आयल के उत्पादन को नई दिशा दी है। राष्ट्रीय तिलहन एवं पॉम ऑयल मिशन के तहत अब तक देशभर में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर पॉम की खेती हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में पॉम ऑयल का घरेलू उत्पादन 15 प्रतिशत बढ़ा हैं। जबकि सरकार ने वर्ष 2029-30 तक इसका उत्पादन 28 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार तेलंगाना, असम, मिजोरम, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पॉम की खेती से रोजगार और आय का नया साधन जुटाने की दिशा में काम कर रही है।

चिंतागुफा में सीआरपीएफ द्वितीय वाहिनी ने की जनसेवा

जगदलपुर,

सीआरपीएफ द्वितीय वाहिनी के कमांडेंट कमलेश कुमार के मार्गदर्शन में वाहिनी द्वारा चिंतागुफा गांव में नागरिक सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिंतागुफा और टोकनपल्ली के सौ से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सामग्री का वितरण किया गया।

सीआरपीएफके कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के मनोरंजन एवं जागरूक्ता के लिए रेडियो का वितरण किया गया, जिसे ग्रामीणों ने बहुत सराहा। इस कार्यक्रम ने सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को और भी मजबूत किया। चिंतागुफा एवं टोकनपल्ली गांव के लोगों ने सीआरपीएफ की इस पहल संतुष्टि जताते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कमांडेंट कमलेश कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सीआरपीएफ स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इस प्रकार के सकारात्मक एवं विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता रहेगा। कार्यक्रम में सहायक कमांडेंट द्वय राजेंद्र कुमार मीना एवं ज्ञानेश प्रताप सिंह, चिंतागुफा थाना प्रभारी गोविंद यादव, चिंतागुफा सरपंच पदमा मासा एवं डी-02 समवाय के अधिकारी व सभी जवान उपस्थित थे।

खास खबर

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एसटी, एससी अभ्यर्थियों को मिलेगा एक लाख का प्रोत्साहन राशि==

0 जिले के इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

कोरबा राज्य शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 उत्तीर्ण करने वाले जिले के पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त 2025 तक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लाक-डी. भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर अपना आवेदन जमा कर सकते है।पावती प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता तथाआवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट ूण्जतपइंसण्बमण्हवअण्पद का विजिट कर अवलोकन व डाउनलोड किया जा सकताहै। उन्होंने जिले के इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा करने हेतु आग्रह किया है।

नेशनल लोक अदालत 13 सितम्बर को

कोरबा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार नेशलन लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर दिन शनिवार को जिला एवं समस्त तालुका स्थित न्यायालयों में किया जायेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में लोक अदालत की तैयारी के संबंध में जिला न्यायालय के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में न्यायिक अधिकारियों, बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में न्यायालयों द्वारा चिन्हांकित प्रकरणों एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के संबंध में चर्चा की गयी।

वन नाईट क्लब फिर बना बवाल का कारण, थार में तोड़फोड़ के मामले में युवती फरार

कोरबा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पॉम मॉल में संचालित वन नाईट क्लब (आएनसी) एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यह क्लब अब शराब और बवाल का अड्डा बनता जा रहा है। हर दिन यहां युवक-युवतियां शराब के नशे में झूमते नजर आते हैं, जिससे आए दिन विवाद और हंगामे की स्थिति बन जाती है। पिछले दिनों भी क्लब के बाहर एक बड़ा बवाल सामने आया था, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान एक महंगी थार वाहन में जमकर तोड़फोड़ की गई।

समिति में सुचारु खाद वितरण से किसानों को मिल रहा लाभ, प्रबंधक ने शासन की नीति को बताया कारगर

किसान हित में राज्य शासन की मजबूत पहल, खरीफ सीजन में किसानों को समय पर मिल रहा खाद

समय पर खाद मिलने से खेती में मिली रफ्तार, किसान दुबराज सिंह ने जताया शासन का आभार

खाद की उपलब्धता समय पर होने से फसल की नींव हुई मजबूतः-किसान बृजपाल राठिया

कोरबा लोकशक्ति।

खरीफका मौसम शुरू होते ही किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफदिखाई देती हैं- खाद, बीज, पानी... सब कुछ समय पर मिले, तभी मेहनत रंग लाती है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है।प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शिता और मंशा के अनुरूप, अन्नदाताओं की परेशानियों को दूर करने खरीफसीजन की शुरुआत से पहले ही सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म की खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण कर दिया गया।

कोरबा विकासखंड की कोरकोमा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में सरकार की किसान हितैषी पहल का स्पष्ट रूप देखने को मिलती है।ग्राम कोरकोमा के किसान श्री दुबराज सिंह राठिया जब समिति में अपने खरीफसीजन में फसल की बेहतर पैदावार के लिए खाद बीज लेने पहुँचे, तो उन्हें बिना किसी परेशानी के डीएपी, यूरिया, एनपीके, सुपर फास्फेट जैसे उर्वरक उपलब्ध हुआ। उन्हें अनावश्यक समितियों के बार -बार चक्कर लगाने नही पड़े। हितग्राही दुबराज सिंह ने बताया कि पहले हमें खाद के लिए समितियों में भटकना पड़ता था, पर इस बार खाद बीज समय पर मिल गया। वक्त पर खाद मिलने से खेती की तैयारी आसान हो गई। खेतों में बुआई का काम पूर्ण हो गया है और अब हम निश्िंचत होकर बेहतर पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं।किसान श्री राठिया ने बताया कि उनकी लगभग 10 एकड़ जमीन है। आज वे समिति से 10 बोरी डीएपी व 5 बोरी यूरिया खाद ले जा रहे है। खाद खरीदने में उन्हें किसी प्रकार की समस्या नही हुई, समिति में आवश्यक दस्तावेज देने के साथ ही तत्काल उन्हें खाद प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले ही वे समिति से 15 बोरी यूरिया, 5 बोरी सुपर फॉस्फेट, 5 बोरी पोटाश ले जा चुके है। आगे भी अपनी आवश्यकतानुसार खाद समिति से ले जाते रहेंगे। किसान दुबराज सिंह राठिया ने समय पर खाद मिलने पर राज्य शासन की किसान हितैषी नीति की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद किया और कहा कि इससे खेती में बहुत सहूलियत हुई है।

कोरकोमा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर ग्राम केराकछार के किसान श्री बृजपाल राठिया ने समिति की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि खाद की उपलब्धता समय पर होने से फसल की शुरुआत अच्छी हुई है। खेतों में बुआई का काम तेजी से हो रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती ० दावा आपत्ति 17 अगस्त तक आमंत्रित

कोरबा एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा ग्रामीण के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पेण्ड्रीडीह में आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद एवं आंगनबाड़ी केन्द्र खोखराआमा, मारगांव, केरवां, दरगा, शांतिनगर, गेंराव, ढोंगदरहा 01, छुईढोढ़ा, डूमरडीह, मसान 01, कुदमुरा 01, सिमकेंदा 02, पेंड्रीडीह और आंगनबाड़ी केन्द्र विमलता में आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक कुल 14 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन मंगाये गये थे।

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (ग्रामीण) से प्राप्त जानकारी के अनुसारप्राप्त आवेदन अनुसार विकासखण्ड स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा प्रावधिक मूल्यांकन प्रत्रक अनुमोदन उपरांतअभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी 17 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय मेंपरियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (ग्रामीण),पता- सखी वन स्टाप सेंटर के आगे नरसिंग गंगा कॉलोनी वार्ड नंबर 35 खरमोरा, कोरबा में अपनी दावा आपत्ति जमा कर सकते है। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निगम के फेस आफ द मंथ चुने गए शांतिलाल, करन व तिलका उत्कृष्ट कार्यो हेतु निगम के छोटे कर्मचारी हो रहे सम्मानित

संवाददाता

कोरबा संवाददाता।

नगर पालिक निगम कोरबा के सहायक ग्रेड-।। शांतिलाल सोनी, सहायक राजस्व निरीक्षक करन पाण्डेय, एवं सहायक ग्रेड-।।। तिलका ध्रुव को अगस्त माह का '' फेस आफद मंथ '' चुना गया है। महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने '' फेस आफद मंथ '' चुने गए इन कर्मचारियों को बधाई दी है तथा कार्य के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि आज से 07 माह पूर्व निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय की विशेष पहल पर निगम का '' फेस आफद मंथ '' चुने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य निगम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मानित करना, उनका उत्साहवर्धन करना एवं अन्य कर्मचारियों को भी इस हेतु प्रेरित व प्रोत्साहित करना था। इसी कड़ी में निगम की सहायक ग्रेड-।। शांतिलाल सोनी, सहायक राजस्व निरीक्षक करन पाण्डेय, एवं सहायक ग्रेड-।।। तिलका ध्रुव को अगस्त माह हेतु निगम का '' फेस आफद मंथ '' चुना गया है।

चयनितों ने जताया आभार - '' फेस आफद मंथ '' चुने गए श्री शांतिलाल सोनी, श्री करण पाण्डेय, एवं श्रीमती तिलका ध्रुव ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि निगम प्रशासन ने हम लोगों के परिश्रम व कार्य के प्रति हमारी निष्ठा के लिए हमें जो सम्मान दिया है, उसके लिए हम निगम प्रशासन के प्रति दिल से आभारी हैं, उन्होने कहा कि हम अपने आपको सम्मानित महसूस कर रहे हैं, हमें इससे यह प्रेरणा मिली है कि हम आगे और भी अधिक अच्छा कार्य करें, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहें।

समिति करती है फेस आफद मंथ का चयन - आयुक्त ने निगम के फेस आफद मंथ के रूप में कर्मचारियों का चयन किए जाने हेतु समिति का गठन किया है। अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता (योजना), उपायुक्त (स्थापना प्रभारी), राजस्व अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी व अध्यक्ष महिला उत्पीडन, उन्मूलन समिति सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं, यह समिति निगम में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यो का आंकलन करते हुए माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 03 कर्मचारियों का चयन '' फेस आफद मंथ '' के रूप में कर रही है।

कर्मचारियों को मिल रहा अच्छे कार्य हेतु प्रोत्साहन - ''

फेस आफद मंथ '' चुने जाने की इस पहल से निगम के अधिकारी कर्मचारियों विशेषकर छोटे कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है तथा उनके बीच अच्छा कार्य करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वहीं जिन कर्मचारियों को '' फेस आफद मंथ '' चुना जाता है, वे अपने आपको सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उन्हें भविष्य में।

पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए 31 तक कर सकते है आवेदन

कोरबा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र जुलाई-जून 2025-26 लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 31 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के दूरवर्ती शिक्षा अंतर्गत अध्ययन केंद्र कोरबा में प्रवेश प्रारंभ है। वर्तमान में अध्ययन केंद्र कोरबा, तहसील रोड, पीजी कॉलेज के बगल में पुराना कलेक्ट्रेट/पुराना आरटीओ (एनसीसी कार्यालय) में संचालित है। प्रवेश अधिसूचना के तहत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एवं कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रमों में स्नातक कोर्स अंतर्गत ,बीए, बीएससी गणित व जीवविज्ञान, बीकॉम (आनर्स) बीबीए(आनर्स), बी-लिब एंड आईएससी, स्नाकोत्तर कोर्स के अंतर्गत एमए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, एमए शिक्षा, एमए छत्तीसगढ़ी, एमएसडब्ल्यू, एमकॉम, एमए/एमएससी गणित व कम्प्यूटर साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अंतर्गत पीजी डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन, डिप्लोमा कोर्स अंतर्गत डिप्लोमा इन योग साइंस, कम्प्यूटर एप्लिकेशन, डिप्लोमा इन साइकोलॉजीकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रामचरित मानस में विज्ञान से सामाजिक उत्थान में डिप्लोमा आदि कोर्स शामिल है। बीकॉम (आनर्स) व बीबीए (आनर्स) स्नातक प्रमाण पत्र कोर्स प्रथम वर्ष दो सेमेस्टर, स्नातक डिप्लोमा दो वर्ष चार सेमेस्टर, स्नातक डिग्री तीन वर्ष 6 सेमेस्टर, स्नातक आनर्स डिग्री चार वर्ष आठ सेमेस्टर, ये दोनों कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित निर्देशों पर सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम है।

जीजामाता मराठा महिला मंडल कोरबा द्वारा भव्य सावन उत्सव का आयोजन

कोरबा संवाददाता

जीजामाता मराठा महिला मंडल, कोरबा के तत्वावधान में सावन उत्सव का आयोजन रविवार को होटल टॉप एंड टाउन में पारंपरिक हर्षोल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज-धज कर कार्यक्रम में शामिल हुईं, जिससे आयोजन में मराठी संस्कृति की अनुपम छटा बिखरी। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना एवं आरती से हुआ। इसके पश्चात मंडल की अध्यक्ष श्रीमती विद्या भोसले एवं महासचिव श्रीमती प्रीति शिंदे के नेतृत्व में उपस्थित मुख्य अतिथि श्रीमती करुणा आहेर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती अर्चना जाधव एवं श्रीमती गीता वाकड़े , श्रीमती पूनम लगड़ का पारंपरिक गीतों एवं पुष्पगुच्छ से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सावन क्वीन चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निर्णायक मंडल की भूमिका में श्रीमती करुणा आहेर, अर्चना जाधव एवं गीता वाकड़े , श्रीमती पूनम लगड़ ने सर्वसम्मति से श्रीमती शुभांगी घाटगे को सावन क्वीन घोषित किया। कार्यक्रम में विविध पारंपरिक एवं मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें भाग लेकर महिलाओं ने उल्लासपूर्वक सहभागिता निभाई। कोषाध्यक्ष श्रीमती अंजनी भोंसले की देखरेख में कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया। अंत में भोज एवं सामूहिक संवाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसकी घोषणा मंडल की जिला महामंत्री श्रीमती प्रीति शिंदे द्वारा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्याएं उपस्थित रहीं, जिनमें प्रमुख रूप से कृभावना भोंसले, गीता निंबालकर, शोभना शिंदे, गीता आहेर, माया हाकरे, निर्मला निंबालकर, सुनीता निंबालकर, रोशनी निंबालकर, संगीता घाटगे, नम्रता शिंदे।

डीएव्ही स्कूल में प्रवेश को लेकर बवाल : स्थानीय अभिभावकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल का किया पुतला दहन

कोरबा । कोरबा स्थित डीएव्ही स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को भारी बवाल खड़ा हो गया। स्कूल प्रशासन पर भ्रष्टाचार, भेदभाव और दुर्व्यवहार के आरोप लगाते हुए स्थानीय अभिभावकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूल प्रिंसिपल का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया गया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल में स्थानीय बच्चों को दाखिले से वंचित किया जा रहा है, जबकि बाहरी और सिफारिशी बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने समय पर आवेदन किया, लेकिन उन्हें सीट नहीं होने का बहाना बताकर टाल दिया गया। वहीं, दूसरे पक्ष के बच्चों को आसानी से दाखिला दिया गया। इस आंदोलन में भू-विस्थापित परिवारों, ैम्ब्स् कर्मियों और अन्य स्थानीय निवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रिंसिपल होश में आओ, स्थानीयों को हक दो, और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए।

गंभीर आरोप :-

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, और धनबल व सिफारिश के आधार पर दाखिले हो रहे हैं। कई अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रवेश के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है।

स्कूल प्रबंधन का जवाब :-

डीएव्ही स्कूल के प्रिंसिपल चंद्रमोहन पांडे ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने एक लिखित बयान में कहा, हमारी स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है, जो प्रवेश समिति द्वारा संचालित होती है। सीमित सीटों के चलते सभी आवेदकों को प्रवेश देना संभव नहीं हो पाता। किसी प्रकार की पक्षपात या भ्रष्टाचार की बात निराधार है। हालांकि, स्थानीय लोग इस बयान से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

नगर निगम कोरबा द्वारा आवारा मवेशियों को सड़कों से उठाने की कार्यवाही लगातार जारी

पशुपालक मवेशियों को सड़क पर खुला न छोड़े अन्यथा होगी दण्डात्मक कार्यवाही

लगभग 200 से अधिक मवेशी शहर की सड़कों से उठाकर पहुंचाएं गए गोकुलनगर गोठान

कोरबा लोकशक्ति।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़कों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले आवारा मवेशियों को सड़कों, सार्वजनिक स्थलों से उठाकर गोकुलनगर गोठान में पहुंचाने की लगातार कार्यवाही की जा रही है। पूरे निगम क्षेत्र में काऊकेचर के माध्यम से निरंतर पशुओं पर नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है, निगम द्वारा वर्तमान में लगभग 200 से अधिक मवेशियों को गोकुलनगर स्थित गोठान में पहुंचाया जा चुका है। वहीं निगम द्वारा पशुपालकों से कहा गया है कि वे अपने मवेशी सड़कों पर खुला न छोड़े, अन्यथा उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ने वाले पशुपालकों को चिन्हांकित कर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही नगर निगम कोरबा द्वारा की जाएगी। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निगम क्षेत्र के समस्त पशुपालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने पालतू मवेशियों को घर पर सुरक्षित रूप से रखें, स्वच्छंद विचरण हेतु सड़कों पर खुला न छोड़े तथा निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही से बचें, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने व यातायात व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। यहाँ उल्लेखनीय है कि पशुपालकों द्वारा अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, आवागमन बाधित होता है, यातायात व्यवस्था बिगड़ती है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल का नुकसान होने व मवेशियों के भी घायल होने की आशंका बनी रहती है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों से इन मवेशियों को हटाने तथा उन्हें गोठान में पहुंचाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, अब निगम द्वारा ऐसे पशुपालकों पर जिनके द्वारा अपने पालतू मवेशी सड़क पर छोड़ दिये जा रहे हैं, उन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पशुपालकों का किया गया चिन्हाकंन- आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम द्वारा क्षेत्र के पशुपालकों, डेयरी संचालकों का नये सिरे से चिन्हाकंन किया गया है तथा पशुपालकों को कड़ी हिदायत दी गई है कि वे अपने मवेशियों को सड़कों पर कदापि खुला न छोड़े। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि निगम क्षेत्र के सभी 07 जोन में पशुपालकों का चिन्हाकंन किया गया है तथा जिन पशुपालकों द्वारा अपने पालतू मवेशी सड़क पर छोड़ दिये जा रहे हैं, उन पर निगम अब दण्डात्मक कार्यवाही भी करेगा।

लैंगिक उत्पीड़न आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक साकेत में सम्पन्न

कोरबा नगर पालिक निगम कोरबा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक बुधवार 06 अगस्त को निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित व्ही.सी. कक्ष में सम्पन्न हुई, समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत व परिवाद न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। निगम में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगम में आंतरिक शिकायत/परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में बुधवार 06 अगस्त को निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के दौरान पाया गया कि समिति के पास इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार का परिवाद लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता साहू, सदस्य सचिव सुभाषिनी आशावान, तारा भगत, कीर्ति अनंत, तिरिथबाई, विनीता सिंह, तुलसीबाई आदि उपस्थित थे

मुख्यमंत्री श्री साय को जशपुर की बहनों ने बांधी राखी

तीन लाख का ईनामी माओवादी शंकर कुरसम गिरफ्तार

बीजापुर, । डीआरजी बीजापुर एवं केरिपु 85 बटालियन की टीम ने पेददापाल एवं हिरमागुण्डा के मध्य जंगल से तीन लाख रूपये के ईनामी जनमिलिशिया कमांडर शंकर कुरसम को गिरफ्तार किया है। शंकर कुरसम लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत तथा क्षेत्र में कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा 10 हजार रुपए का ईनाम भी उद्घोषित है।

जिले में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत् डीआरजी बीजापुर एवं केरिपु 85 बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा माओवादी विरोधी अभियान के दौरान पेद्दापाल एवं हिरमागुण्डा के मध्य जंगल से 01 सक्रिय माओवादी को पकड़ा गया है। माओवादी की पहचान शंकर कुरसम पिता पाण्डू कुरसम उम्र 36 वर्ष निवासी इसुलनार थाना बीजापुर जिला बीजापुर के रूप में हुई है। माओवादी शंकर कुरसम थाना बीजापुर क्षेत्रान्तर्गत पेद्दाकोरमा - बोड़ला पुसनार के जंगल में दिनांक 29/07/2025 को पुलिस और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ की घटना में शामिल था। लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत गिरफ्तार माओवादी निम्नलिखित गंभीर घटनाओं में संलिप्त रहा है। शंकर 23 दिसंबर 2023 को ग्राम मनकेली में छोटू कुरसम की हत्या में शामिल था। 25 दिसंबर 2023 को गोरना-मनकेली मार्ग पर आईइडी ब्लास्ट की घटना में भी शामिल था जिसमें डीआरजी का एक जवान घायल हुआ था।

(बीजापुर) सर्पदंश से चेरपाल पोटाकेबिन के दो छात्र हुए शिकार, एक की मौत, दूसरा गंभीर

बीजापुर, जिले के चेरपाल पोटाकेबिन के दो छात्र राखी की छुट्टी लेकर नाना के साथ अपने अंदरूनी गांव गमपुर के लिए निकले थे, जहां वे ज्यादा रात होने के कारण पीडिया गांव में ही सो गए । रात को सोते समय दोनों छात्र समीर कड़छी व रामलू मड़काम उम्र 12 वर्ष को जहरीले सांप ने डस दिया, जिससे एक छात्र की मौत हो गई । दूसरे छात्र रामलू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बीजापुर में इलाज बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने पहले अस्पताल न लाकर गांव में झाड़ फूंक करके बचाने की कोशिश की, लेकिन एक छात्र को बचा नहीं पाए। दूसरे छात्र को गंभीर हालत में बीजापुर लाया गया, जहां इलाज के बाद उसे जगदलपुर रेफर किया गया ।

उप मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला स्व सहायता के माध्यम से रोजगार पर की चर्चा

जगदलपुर, 08 अगस्त (आरएनएस)। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला कार्यालय के आस्था सभाकक्ष में आज शुक्रवार को बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में एसआरएलएम और एनआरएलएम की फील्ड विजिट टीम के साथ चर्चा की । इस दौरान कलेक्टर हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता व अन्य उपस्थित रहे ।

नवम अग्र अलंकरण समारोह का आयोजन 28 को

रायपुर, । छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल सभा द्वारा 28 अगस्त को एमएन पैलेस में नवम अग्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह अलंकरण 18 विभिन्न क्षेत्रों में किये गये सामाजिक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रदाय किया जाएगा। संस्था के पदाधिकारी अशोक लोहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अलंकरण आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। एक जून 2024 से 30 जून 2025 के मध्य किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रतिभागियों को 11 हजार रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रचार प्रसार प्रभारी अशोक लोहिया के अनुसार समारोह में शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा पर्यावरण महिला सशक्तिकरण उद्योग व्यापार खेल आदि क्षेत्रों में अग्रदीप अग्रभूषण जैसी उपाधियों से सम्मानित किया जाएगा।

नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए बन रहे तीन हजार पीएम आवास

रायपुर, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचलों के हर परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने सरकार लगातार पहल कर रही है। राज्य में नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष परियोजना के तहत करीब तीन हजार आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए विशेष परियोजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत कराया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को गंभीरता से लेकर पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराएं कलेक्टर्स - मुख्यमंत्री

0 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ किया गया

0 अनुसूचित जाति वर्ग के पांच युवाओं को हर साल पायलट बनाने दी जाएगी आर्थिक सहायता

0 गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कोचिंग के लिए 50 लाख रुपए की दी गई स्वीकृति

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर वर्ष समय पर आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हम बाबा गुरु घासीदास जी के 'मनखे-मनखे एक समान' के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले को इस बैठक के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अब समय आ गया है कि हम विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में विकास के कार्य हुए हैं। अनुसूचित जाति समाज के समुचित विकास के लिए प्राधिकरण एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, अजा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता, तथा जोड़ा जैतखंभ के निर्माण में सीमेंट के साथ-साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही, दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में 'नालंदा परिसर' के निर्माण की भी बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों के वर्षों से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इन कार्यों का समय पर पूर्ण न होना चिंता का विषय है।

बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में स्पष्ट है। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और सभी समाज को साथ लेकर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का संकल्प दोहराया।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने गिरौधपुरी धाम में रोपवे निर्माण, मेला आयोजन के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जोक नदी के पास स्नान हेतु आवश्यक व्यवस्था, ठहरने की सुविधा, जोड़ा जैतखंभ में लकड़ी के उपयोग, बाराडेरा धाम में ऐतिहासिक तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जैसी मांगें बैठक में रखीं। उन्होंने बजट वृद्धि और मांगों की स्वीकृति के लिए भी आभार व्यक्त किया।बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधानों की जानकारी, एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित नागरिक सुविधाओं, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, और शैक्षणिक सुविधा विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई।

राखी बनाओ प्रतियोगिता में छाया भंडारी रही प्रथम

नगरी/सिहावा,जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में डाइट नगरी के प्राचार्य श्री प्रकाश राय के निर्देश पर एवं डाइट नगरी के कार्यक्रम प्रभारी जोहन नेताम के मार्गदर्शन पर नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यवसासिक शिक्षा अंतर्गत राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया द्य कार्यक्रम में अतिथि डाइट प्राचार्य एवं राजेश तिवारी प्र. प्राचार्य हाई स्कूल खलारी एवं संकाय सदस्यों का तिलक वंदन एवं गुलदस्ता से स्वागत किया गया द्वितीय वर्ष के छत्राध्यापक छाया देवांगन द्वारा सुमधुर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया डाइट नगरी के प्रार्थना कक्ष में श्री राजेश तिवारी प्र.प्राचार्य हाई स्कूल खलारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा का ध्वज सहिता, बाँधने बाँधने के नियम का ट्रेनिंग दिया गया ताकि छात्राध्यापक भविष्य में शिक्षक बने तो ध्वज सहिता का पूरा ज्ञान हो इस कार्यक्रम का लाभ सभी छात्राध्यापक उत्साह से भाग लिए एवं धव्ज सहिता पर अपनी पूरी समझ बनाए द्य कार्यक्रम के द्वितीय कालखंड में रक्षाबंधन त्यौहार पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया और राखी बनाओ प्रतियोगिता में डाइट नगरी के द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक एवं डाइट नगरी के संकाय सदस्य उपस्थित थे इस प्रतियोगिता में सभी भावी शिक्षक बहुत ही उत्साह से भाग लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया इस एक घंटे में सभी छात्राध्यापक बहुत ही सुन्दर -सुन्दर राखी बनाकर प्रदर्शन के लिए डाइट परिसर में स्टाल लगाया गया.

सारे जरूरी काम छोड़ घायल जवान से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मेयर पाण्डेय भी रहे साथ

शर्मा ने घायल जवान से की मुलाकात, कहा- पूरी सरकार है आपके साथ

फिर नजर आई गृहमंत्री शर्मा की संवेदनशीलता

जगदलपुर,संवाददाता।

छत्तीसगढ़ के संवेदनशील और सहृदय उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की संवेदनशीलता की एक झलक यहां फिर देखने को मिली। विजय शर्मा इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा को जैसे ही पता चला कि नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती कराया गया है, अपने सारे जरूरी काम छोड़कर श्री शर्मा तुरंत महापौर संजय पांडे को लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गए। घायल जवान से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घायल जवान और उनके परिजनों से कहा कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, पूरी सरकार और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता आपके साथ हैं। आप जैसे वीरों के अदम्य साहस के बल पर ही हमारा बस्तर और छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होने जा रहा है। आप लोग बस्तर के आदिवासियों और यहां

के अन्य मूल निवासियों की भलाई तथा बस्तर की बेहतरी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका यह योगदान छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा याद रखेगी। जवान के इलाज और सुविधाओं में जरा कमी तथा अस्पताल की अव्यवस्था देख उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बेहद नाराज हो उठे। उन्होंने डाक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि जो जवान आप और हम सबकी हिफाजत तथा बस्तर के समग्र विकास की राह खोलने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी देखभाल में कोताही नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो यह हमारी कृतघ्नता ही कहलाएगी। अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें। श्री शर्मा ने डॉक्टर्स को घायल जवान के साथ ही हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धमतरी जिले के कुरूद में वित्तीय समावेशन शिविर का सफल आयोजन

240 खातों का पुनः KYC संपन्न, रिज़र्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक ने की सराहना

धमतरी, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत कुरूद विकासखंड के डांडेसरा ग्राम पंचायत में 08 अगस्त को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा, कुरूद शाखा द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस विशेष शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना एवं पात्र खातों का पुनः-चिह्नष्ट करना रहा। शिविर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती रीनी अजित द्वारा शिविर का दौरा किया गया। उन्होंने शिविर की गतिविधियों की समीक्षा की तथा बैंक अधिकारियों एवं लाभार्थियों से संवाद कर वित्तीय समावेशन के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। श्रीमती रीनी अजित ने खाताधारकों से अपील की कि वे समय रहते पुनः-चिह्नष्ट की प्रक्रिया पूर्ण करें जिससे उनके खाते सक्रिय बने रहें। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के आयोजन की पूर्व सूचना ग्रामवासियों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी प्रयास करें। शिविर के दौरान लाभार्थियों को भारतीय रिज़र्व बैंक की एकीकृत ऑम्ब्ड्समैन योजना 2021, निष्क्रिय खाते पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया, डिजिटल बैंकिंग में सावधानी, तथा डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री इंद्रकुमार टिलवानी बताया इस शिविर में कुल 240 खातों का सफलतापूर्वक पुनः-चिह्नष्ट किया गया, जो कि अभियान की सफलता की दिशा में एक सराहनीय उपलब्धि है। यह शिविर न केवल बैंकों और लाभार्थियों के बीच संपर्क का सशक्त माध्यम बना, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय जागरूकता को भी नई दिशा मिली। सरकार एवं बैंकिंग संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से समावेशी विकास की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने किया स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण

सुकमा,। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सुकमा द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोरनापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंतागुफा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंटलनार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगरगुंडा, उप स्वास्थ्य केंद्र सिलगेर एवं उप स्वास्थ्य केंद्र कोण्डासावली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आधार बेस उपस्थिति, नेक्स-जेन एवं आभा आईडी आधारित पंजीयन, प्रसूता महिलाओं की सुविधाएं तथा स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत स्थिति की समीक्षा की गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोरनापाल

यहां 10 कर्मचारियों का आधार बेस अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पा रहा था, जिनमें 04 मातृत्व अवकाश, 01 अर्जित अवकाश पर और 05 कर्मचारियों के मोबाइल में तकनीकी समस्या पाई गई। 02 प्रसूता महिलाएं भर्ती थीं जिनके पास आयुष्मान कार्ड, एमसीपी कार्ड एवं राशन कार्ड नहीं था। आयुष्मान कार्ड मंगवाकर ब्लॉकिंग करने के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंतागुफा

निरीक्षण में 02 प्रसूता महिलाएं भर्ती थीं, जिनमें से एक ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। दोनों महिलाओं के पास आयुष्मान एवं राशन कार्ड नहीं था, जिस पर कार्ड मंगवाकर

ब्लॉकिंग करने निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन आधार बेस उपस्थिति एवं नेक्स-जेन, आभा आईडी से ओपीडी पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिंटलनार

कर्मचारियों को प्रतिदिन आधार बेस उपस्थिति दर्ज करने और नेक्स-जेन, आभा आईडी से पंजीकरण करने निर्देशित किया गया। यहां शासकीय आवास की सुविधा न होने से सभी कर्मचारी 1 किमी दूर बस्ती में रहते हैं, जिससे रात में मरीजों और स्टाफको असुविधा होती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगरगुंडा

स्वयं का भवन नहीं होने के कारण केंद्र का संचालन 5-बेड प्रीबर्थ वेटिंग हॉल में किया जा रहा है। आवास की कमी से एक आवास में 3-3 कर्मचारी रहते हैं। नेटवर्क सुविधा के अभाव में आधार बेस उपस्थिति एवं ऑनलाइन पंजीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप आयोजित करने निर्देश दिए गए।

उप स्वास्थ्य केंद्र सिलगेर

कर्मचारी उपस्थित पाए गए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्र में निवासरत हैं, जबकि पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी वहीं निवास करने निर्देशित किया गया। यहां आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य जारी है। भवन एवं आवास निर्माण की आवश्यकता बताई गई।

उप स्वास्थ्य केंद्र कोण्डासावली

सीएचओ उपस्थित पाई गईं। यहां प्रतिदिन 25-30 ओपीडी और प्रतिमाह 3-5 संस्थागत प्रसव हो रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आवश्यक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और मरीजों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एम-पैक्स के व्यापार विविधीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

महासमुंद,राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गुरुवार को महासमुंद में एम-पैक्स के व्यापार विविधीकरण विषय पर एक दिवसीय भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एवं सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंत्रालय की 60 नई पहलों में से एक के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न पैक्स के 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पैक्स एवं एफपीओ सदस्यों को व्यापार विविधीकरण के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना था।

कार्यक्रम के संयोजक एवं एनसीडीसी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक श्री किंचित जोशी ने प्रतिभागियों को सत्रों को ध्यानपूर्वक सुनने, समझने एवं विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने एनसीडीसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का भी आवाहन किया। विशिष्ट अतिथि श्री द्वारिका नाथ, उपायुक्त (सहकारिता) एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, महासमुंद ने सहकारिता मंत्रालय की पहलें, मॉडल उपनियम, सीएसी संचालन तथा पैक्स कम्प्यूटरीकरण पर व्याख्यान दिया। दूसरे सत्र में श्री अविनाश शर्मा, नोडल अधिकारी, डीसीसीबी रायपुर शाखा महासमुंद ने एम-पैक्स पर अपने विचार साझा किए। वहीं, श्री प्रियव्रत साहू, डीडीएम नाबार्ड, महासमुंद ने कृषि यंत्रीकरण, गोदाम निर्माण, मत्स्य पालन, डेयरी आदि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के अवसरों पर चर्चा की।

अंतिम सत्र में एनसीडीसी की विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय सहायता की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा उपयुक्त प्रस्ताव सृजन हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार 2025 के लिए शीघ्र आवेदन भेजने का आह्वान भी किया गया।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)